



लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com



मनु ने सरबजोत के साथ कांस्य जीत रचा इतिहास स्पोर्ट्स-12

वायनाड में भूस्खलनों से भारी तबाही, 123 लोगों ने गंवाई जान

● मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, बहुत से शव मलबे में दबे, राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना

कुमार चेलप्पन। कोच्चि

केरल के उत्तरी क्षेत्र में वायनाड जिले की मुंडक्कई बस्ती में मंगलवार तड़के हुए दो भीषण भूस्खलनों में 123

लोगों की जान चली गयी और सैकड़ों घर धराशायी हो गए। 128 लोग घायल हुए हैं। बचावकर्मियों ने कहा कि मरने वालों की संख्या मंगलवार शाम छह बजे पता चली संख्या से अधिक हो सकती है। रविवार सुबह से राज्य में मूसलाधार बारिश हो रही है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार शाम मीडिया को जानकारी देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि कई शव

जमीन के नीचे दबे हुए हैं और लगातार बारिश और खराब रोशनी के बावजूद शवों को निकालने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुंडक्कई में क्रमशः 2 बजे और 4 बजे दो भूस्खलन हुए। सारी जनता सो रही थी और उन्हें आने वाली विपत्ति का पता चलने की कोई संभावना नहीं थी। यह राज्य द्वारा अनुभव की गई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। विजयन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था और हर संभव मदद की पेशकश की थी। विजयन ने



केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है।

अफसोस जताया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि राज्य अकेले बचाव और पुनर्वास कार्य नहीं कर सकता। भूस्खलन के कुछ घंटों के भीतर, केंद्र सरकार ने बाढ़ के पानी, मिट्टी और चट्टानों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात किया। ऊंची पर्वतमालाओं पर स्थित मुंडक्कई के निवासियों के अलावा, क्षेत्र के सैकड़ों हाई-एंड रिसॉर्ट्स में रहने वाले कई छुट्टियां मनाते वाले भी भूस्खलन में फंस गए हैं। भारतीय वायु सेना ने

बचाव अभियान के लिए अपने सुलुवर बेस से दो हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। डिफेंस पीआरओ के अनुसार, 122 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) मद्रास के सेकेंड-इन-कमांड के नेतृत्व में 43 कर्मियों की एक टीम को तैनात किया गया है। एक चिकित्सा अधिकारी, दो जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और 40 सैनिकों वाली टीम प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए सुसज्जित है। जिला प्रशासन ने कहा कि इसके अलावा, सेना का इंजीनियरिंग समूह (श्रेष पेज 9)



झारखंड के सरायकेला-खरसावा में ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है।

झारखंड में हावड़ा-मुंबई मेल ब्रेकरी हुई, दो लोगों की मौत

पायनियर समाचार सेवा। जमशेदपुर

झारखंड के सरायकेला-खरसावा जिले में मंगलवार तड़के हावड़ा-मुंबई मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत, जमशेदपुर से लगभग 80 किमी दूर बाराबाबू के पास सुबह 3.45 बजे हुई। एसईआर के एक अन्य अधिकारी ने कहा, रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना की जांच की घोषणा की है। पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा, हावड़ा-मुंबई मेल के 18 डिब्बे बाराबाबू के पास पटरी से उतर गए, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। उन्होंने कहा, हावड़ा-मुंबई ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 16 यात्री डिब्बे, एक पावर कार और एक पेंट्री कार थी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और घायल लोगों की मदद करने का निर्देश दिया। रेलवे ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये, गंभीर चोटों वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपये, मामूली चोटों वाले लोगों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। रेलवे सीपीआरओ के मुताबिक, बचाव और राहत कार्य पूरा कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को दोपहर 12.15 बजे चक्रधरपुर से एक विशेष ट्रेन द्वारा उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। दुर्घटना के कारण एसईआर ने कुछ एक्सप्रेस और यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया। ये हैं 22861 हावड़ा-टिटलागढ़-कांतबाजी एक्सप्रेस, 08015/18019 खड़गपुर-झारखाम-धनबाद एक्सप्रेस, 12021/12022 हावड़ा-बाराबिल-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, 18109 टाटानगर-इलाहाबाद एक्सप्रेस और 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस। कांग्रेस ने झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जून के बाद से 'असफल मंत्री' ने 'तीन दुर्घटनाओं की निगरानी की' जिसमें कुल मिलाकर 17 लोगों की जान की जा गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में 'कोई जवाबदेही नहीं' है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सिलसिलेवार ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और आश्चर्य जताया कि क्या केंद्र की उदासीनता का कोई अंत नहीं होगा।

योगी सरकार ने पारित किया सख्त 'लव जेहाद' कानून

● अवैध धर्मांतरण पर उम्रकैद के प्रावधान वाला संशोधित बिल विधानसभा में पारित

● नकल माफिया पर नकेल कसेगा नया कानून

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिससे धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कानून सख्त हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सदन में उत्तर प्रदेश विधिविधेयक, 2024 पेश किया। हालाँकि, इस कदम की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। वहीं उत्तर प्रदेश सर्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक- 2024 भी पास हो गया। दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सोमवार



लखनऊ में मंगलवार को विधानसभा में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

को सदन में पेश किया गया था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए।

पहले किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम सजा 10 साल और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग, विकलांग या मानसिक रूप से विशिष्ट व्यक्ति, महिला

या एससी-एसटी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी उससे शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से, किसी व्यक्ति को उनके जुमाने का प्रावधान था। नए प्रावधानों के धमकी देता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, शादी का वादा करता है,

किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को लालच देता है या उसकी तस्करी करता है, तो उन्हें 20 तक की सजा दी जाएगी। वर्षों की कैद, सजा एक साल से कम नहीं होगी और इसे आजीवन कारावास (मृत्यु तक) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पीड़िता के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि धर्मांतरण के मामलों में कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 4 कहती है कि केवल वह व्यक्ति जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति जो रक्त, विवाह या गोद लेने से उससे संबंधित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है।

इसके अलावा, विधेयक का उद्देश्य गैरकानूनी धर्मांतरण उद्देश्यों के लिए विदेशी या अवैध संगठनों से धन प्राप्त करने का एक नया अपराध जोड़ना है। अपराधियों को 5 साल से 14 साल के बीच जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई नए न्यायालय से नीचे की किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जाएगी और इसके साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना (श्रेष पेज 9)



नई दिल्ली में मंगलवार को लोकसभा में विचार व्यक्त करती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

'बेहतर नीतियों से भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था'

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

लोकसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 2024-25 के 48.21 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी। निचले सदन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट को भी ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। केंद्रीय बजट और जम्मू-कश्मीर का बजट लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी सदन द्वारा पारित किये गये। बहस का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को 2024-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत तक और 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रस्ताव है। बजट पर मैरदान बहस और चर्चा के अपने जवाब में, सीतारमण ने विपक्षी नेताओं के भ्रामक दावों को गलत बताया कि यदि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं लिया जाता है, तो उसे कोई बजटीय आवंटन नहीं मिलता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी राज्य को धन देने से इनकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले बजटों में यूपीए सरकार ने भी अपने बजट भाषण में सभी राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया था।

सीतारमण ने कहा कि सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के कारण कोविड महामारी के बाद भारत ने उन्नी वृद्धि हासिल की और आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने लोकसभा में बजट 2024-25 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है, उसे कोई आवंटन नहीं हुआ है। सीतारमण ने कहा, चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए के बजट में सामाजिक और भौगोलिक समावेश पर जोर है। यानी हर वर्ग और क्षेत्र का ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के कारण महामारी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। सीतारमण ने कहा, हमारी आर्थिक वृद्धि न केवल बेहतर है बल्कि हम राजकोषीय घाटे को कम करने के रास्ते पर भी हैं। उल्लेखनीय है कि 2023-24 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर श्रेष पेज 9)

राउज स्टडी सर्किल हादसे के आठ कारण

● मुख्य सचिव ने मंत्री आतिथी को अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी

संजय राय। नई दिल्ली

राउज स्टडी सर्किल में शनिवार देर शाम को हुए हादसे ने देश को झकझोर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के चौबीस घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सोमवार देर रात राजस्व मंत्री आतिथी को हादसे से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और नालों की डिजिटलिंग को लेकर सिलसिलेवार कटाक्ष करते हुए कहा कि जून के बाद से 'असफल मंत्री' ने 'तीन दुर्घटनाओं की निगरानी की' जिसमें कुल मिलाकर 17 लोगों की जान की जा गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में 'कोई जवाबदेही नहीं' है।

रिपोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया है कि इस जांच के दौरान यह पता चला कि यह राउज दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती



नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में तीन आईएसए अव्यर्थियों की मौत के बाद प्रदर्शन करते छात्र।

है। ऐसे में एमसीडी से भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेंट्रल जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से इस घटना को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

अंतरिम जांच रिपोर्ट में बेसमेंट में पानी घुसने और हादसे की 8 वजहों का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह सड़क व्यवसायिक सड़क के रूप में नोटिफाइड है। अधिकांश संपत्तियों को

कमर्शियल प्रतिष्ठानों में परिवर्तित कर दिया गया है। भवनों के बाहर फुटपाठ पर ग्रेनाइट, मार्बल और कोटा स्टोन लगाकर रैप का निर्माण किया है। जिसकी वजह से नाले की सफाई नहीं हो सकती। शंकर रोड से पूसा रोड तक सड़क की रूपरेखा तशरीनुमा है, जिसका सबसे निचला हिस्सा राउज आईएसए सड़क के सामने है। भारी बारिश के दौरान करीब 200 फुट लंबे हिस्से में पानी जमा हो जाता है। जब भी वाहन यहां

वैश्विक निवेशक भारत की तरफ देख रहे, अवसर को न गवाएं : मोदी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत को विकास और स्थिरता का प्रतीक बताते हुए कहा, जब पूरा विश्व उच्च मुद्रास्फीति और कम विकास दर का सामना कर रहा है ऐसे में देश अगले पांच वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 8 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है और वह दिन दूर नहीं जब देश वर्तमान पांचवें स्थान से वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने यह दावा किया, वैश्विक निवेशक भारत को निवेश गंतव्य (इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन) के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने घरेलू उद्योग से

'विकसित भारत' की यात्रा का हिस्सा बनने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) द्वारा 'विकसित भारत की ओर यात्रा' विषय पर बजट-के बाद आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास की कहानी की मुख्य प्रेरक शक्ति धन सृजनकर्ता होते हैं, ऐसे समय में भारत की नीतियां, प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, निर्णय और निवेश वैश्विक प्रगति का आधार बन रहा है। मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत और आपकी (उद्योग) ओर देख रहा है। सरकार की नीतियां और प्रतिबद्धता और निवेश वैश्विक विकास की नींव बन रहे हैं। दुनिया भर के निवेशक भारत आने के लिए उत्सुक हैं। विश्व के नेता भारत के प्रति

सकारात्मकता से भरे हुए हैं। यह भारतीय उद्योग के लिए सुनहरा अवसर है और हमें इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। वैश्विक निवेशकों के बीच भारत में बढ़ती रुचि की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग को हाल ही में नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों से निवेशक-अनुकूल चाट्टर (संहिता) बनाने, निवेश नीतियों में स्पष्टता लाने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए गए उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति के साथ भारत ऐसे विश्व में विकास और स्थिरता का प्रतीक है, जो उच्च मुद्रास्फीति और कम विकास तथा अन्य भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 8 प्रतिशत की दर से विकास



नई दिल्ली में सीआईआई पोस्ट बजट सम्मेलन में विचार व्यक्त करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

कर रहा है और वह दिन दूर नहीं जब देश वर्तमान पांचवें स्थान से वैश्विक स्तर पर

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यह उपलब्धि उनके मौजूदा तीसरे कार्यकाल में हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है और वह सभी निर्णय 'राष्ट्र विकास और रोजगार पर अत्यधिक ध्यान' लेंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्र प्रथम को प्रतिबद्धता 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, संतुष्टि दृष्टिकोण, शून्य प्रभाव-शून्य दोष पर जोर और आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत के संकल्प में परिलक्षित होती है। मोदी ने कहा कि घरेलू उद्योग को सरकार के साथ मिलकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और इसे उभरते क्षेत्रों में वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उन्होंने बजट

में घोषित विभिन्न उपायों को भी याद किया, खासकर एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो करोड़ों रोजगार पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग 4.0 मानकों को ध्यान में रखते हुए कोशल प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केंद्रित कर रही है। भारत में 1.40 लाख स्टार्टअप हैं जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और 8 करोड़ से अधिक लोगों ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजनाओं की मदद से नया व्यवसाय शुरू किया है। इस वर्ष के बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के बहुप्रशंसित प्रधानमंत्री पैकेज का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे 4 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, पीएम पैकेज समग्र और व्यापक है। (श्रेष पेज 9)

महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा: योगी

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर किया बड़ा प्रहार

● कहा, महिला संबंधी अपराधों के मामलों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही इनवॉल्व

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान सभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लगातार कमी आ रही है। अपराधियों के मन में कार्रवाई का भय है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर सरकार आने के बाद सबसे पहले हमने शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्कैंडल इसका एक उदाहरण है। बताते हुए दुख होता है कि एंटी रोमियो स्कैंडल का जब गठन हुआ तब सबसे पहले इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने ही किया था। ये बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराधों के मामलों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही इनवॉल्व पाए जाते हैं। महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये लोग सुरक्षा की बात क्या करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए ये समाजवादी खुद ही एक गंभीर खतरा हैं। इसलिए महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत और सक्रिय है। हमारी सरकार प्रदेश में हर बेटी को और हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम योगी ने सदन में कहा कि महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे दो प्रकार के होते हैं। एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर। दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। 2016 से जल्द ही दो सप्ती तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। 2016 की तुलना में दहेज रजिस्ट्री घटनाओं के बारे में देखें तो 2023-24 के बीच में लगभग 17.5 प्रतिशत की कमी आई है। 2016 की तुलना में 2023-24 में बलात्कार की



5 वर्षों में की महिला पुलिस कार्मिकों की दोगुनी भर्ती

सीएम योगी ने बताया कि 2020 से हमारी सरकार ने मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई है। 2017 के पहले तक कुल 10 हजार महिला कार्मिकों की भर्ती हुई थी, जबकि 2017 से 2022-23 के बीच प्रदेश में 20 हजार से अधिक महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफलता प्राप्त हुई है। यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी महिला पुलिस कार्मिकों की भर्तियां हुई थीं, उससे दोगुनी भर्ती महज 5 वर्षों में हमने की है। पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 20 प्रतिशत हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की व्यवस्था प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएस के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुईं वो केवल ऑफिस या थाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में भी सहयोगी बने, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10 हजार से अधिक महिला बीट स्टेशन तैयार किए गए, महिला पंचक बूथ की स्थापना की गई। ये भी व्यवस्था की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी मिशन शक्ति के अंतर्गत हर सप्ताह महिलाओं के पास जाएं और महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा करें। यही नहीं, मुद्दों के समाधान के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके स्वावलंबन से संबंधित योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराएं।

घटनाओं में 25.30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 2017 से लेकर 2024 के बीच में जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश सरकार ने अपने प्रतीक्यूशन विंग को मजबूत किया है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। इस दौरान 24 हजार 402 प्रकरणों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 2017-24 के बीच पॉक्सो एक्ट में 9875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 2024 के मध्य महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिसमें 21 को मृत्युदंड, 17,013 को आजीवन कारावास, 4653 को दस वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को दस वर्ष से कम के कारावास की सजा दी गई है। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में इस दिशा में कई अन्य प्रयास भी हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग सिस्टम फॉर सेन्सुअल ऑफेंसिव को लेकर भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है उसको हमने 2018 में ही एक्टिव कर दिया है।

रसोइया, आंगनबाड़ी, बीसी सखी से जुड़ी महिलाओं को अतिरिक्त आय से जोड़ रही सरकार

परिषदीय स्कूलों में रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय से जुड़े एक सवाल पर सीएम योगी ने फिर एक बार सपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब रसोइयों को जो मानदेय मिलता था वो 500 रुपए से भी कम था। आप लोगों ने दूसरा अन्याय उनके साथ ये किया कि जिसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, वहीं इनके चयन में भी भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने 2022 में उनके मानदेय को न्यूनतम 2 हजार रुपए किया। इन सभी ने कोरोना कालकंड में अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने में अभिर्नंदनीय काम किया है। यही वजह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों या आंगनबाड़ी सहयोगी हों, इन सब के मानदेय में वृद्धि भी की है और इन्हें टैब्लेट से आच्छादित करने के साथ साथ अतिरिक्त आय का प्रावधान भी किया है। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को ही स्वावलंबी बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके। वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है। बीसी सखी रखी गई है, जो गांव के अंदर बैंकिंग लेनदेन का कार्य करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक साढ़े 15 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। पंचायत सहायक को भी हम 6 हजार रुपए प्रतिमाह देते हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल और अन्य सभी योजनाओं को जिनकी वह ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध कर रहा है एक अतिरिक्त आय भी होती है।

अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है समाजवादी पार्टी: सुरेश खन्ना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला बाल अपराधों से जुड़े मामले को लेकर सरकार को घेरने का जबरदस्त प्रयास किया लेकिन यह दांव सपा को ही उल्टा पड़ गया। प्रश्न प्रहर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय व रागिनी सोनकर सहित सपा के कई सदस्यों ने प्रदेश में बाल और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकार को सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया। सपा सदस्यों का कहना था कि सरकार के दावों के बावजूद महिला और बाल अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों में सरकार का कोई खौफ नहीं है। जिस समय सपा के सदस्य यह मामला सदन में उठा रहे थे उस समय नेता सदन और

सपा ने सरकार के प्रयासों को बताया नाकाफी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इसलिए इस मुद्दे पर नेता सदन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जवाब देते हुए सबकी बोलती बंद कर दी। प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई पर उठाए गए सवाल पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बलिया में अवैध वसूली मामले में कार्रवाई हुई। योगी की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देने वाली है। कहा था मिट्टी में मिला देंगे तो मिला दिया। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। यूपी में जोरो टॉलरेंस की जो नीति साल 2017 में शुरू हुई थी, वह आज भी कायम है।

हर घर जल योजना का 84.56 प्रतिशत कार्य हो चुका है पूरा: स्वतंत्र देव

प्रश्न प्रहर में सपा के फहीम इरफान, अनिल प्रधान, कांभ्रिस की आराधना मिश्रा मोना ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर-घर-हर नल योजना पर सवाल करते हुए कहा कि नल के बिछने से पूर्व पाइप लाइन के खोदी जा रही गांवों की सड़कों का बुरा हाल है। इस पर जलशक्ति मंत्री स्वंत्रदेव सिंह ने कहा कि हर घर जल योजना का कार्य 84.56 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस साल इस योजना को शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। जहां गांवों में गड्डों की बात है तो उन्हीं भी जल्द ही डुरुस्त कर लिया जाएगा। सपा के समरपाल सिंह ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का मामला उठाया। जवाब में बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस संबंध में सरकार के पास प्रस्ताव विचारार्थी नहीं है। सपा के पंकज मलिक ने हर जिले में पृथक विद्यालय खोले जाने की योजना शुरू किए जाने की बात कही इस पर माध्यमिक शिक्षामंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही जिलों में संचालित है। इसलिए अलग से इसकी व्यवस्था किए जाने कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिलेश और शिवपाल पर कसा तंज

सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल पर तंज कसा। सदन की कार्यवाही के दौरान जब नव नियुक्त नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सीएम योगी से महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर जवाब मांगा तब सीएम योगी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बजाई देते हुए इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर व्यंग्य बाण चला दिए। सीएम योगी ने सदन में व्यंग्य कसते हुए कहा कि आपके चयन के लिए बधाई देता हूं। ये अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। दरअसल, सीएम योगी ने यह व्यंग्य इसलिए दिया, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल यादव की जगह माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष के लिए चयनित किया। इसी पर उन्होंने शिवपाल यादव पर चुटकी ली।

योगी सरकार ने पेश किया 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट



युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर फोकस, प्रदेश के विकास को लगेगे पंख

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को और गति देने, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए विधानसभा में मंगलवार को 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखा व्यय 4 हजार 227.94 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट में 7500.81 करोड़ औद्योगिक विकास, 2000 करोड़ ऊर्जा विभाग, एक हजार करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना को सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिये हैं। इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुसंधान के लिए 2.79 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़, विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्प्यूटेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना, उपकरणों के विस्तार के लिए 2.45 करोड़ दिये हैं।

धर्मांतरण कानून के बहाने प्रदेश की जनता पर पुलिस राज थोपने की कोशिश: आराधना मिश्रा



कांग्रेस नेता ने की धर्मांतरण कानून पर समर्थन देते हुए आयोग बनाने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस विधानमंडल दल नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने धर्मांतरण कानून में लाए गए संशोधन पर भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस कानून के बहाने लोगों के अधिकारों को समाप्त कर पुलिस स्टेट थोपने का आरोप लगाया है, और प्रदेश में हो रहे पेपर लोक पर भाजपा सरकार को घेरा है और नकल माफियाओं पर कार्यवाही में लापरवाही का निष्पक्ष पालन न करने का आरोप लगाया है। आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा की केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल योजना की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। और आज पेश किए गए अनुपूरक बजट पर चुटकी लेते हुए आराधना मिश्रा मोना ने इसे सिर्फ

दिखावा करार दिया है और मुख्य बजट के खर्च पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून को कटघरे में खड़ा करते हुए इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए और कहा कि इस कानून के बहाने भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों पर पुलिस राज थोपने का प्रयास है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में तमाम खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों के जो मूल अधिकार है उनका हनन भी हो रहा है जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का भी अपमान हो रहा है हर व्यक्ति को अपनी बात, अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन इस संशोधन विधेयक में एफआईआर लिखते ही तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और उस व्यक्ति की जमात बिना सरकारी वकील को सुने रोकना न्याय विधान के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।

पायनियर वर्गाकृत

सूचना

मैंने अपने पुत्र हरीप्रतिल सिंह व उसकी पत्नी जुगताज कोर को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इसकी किस्ती भी कायं व लेन-देन से मेरे व मेरे परिवार और मेरे बेटियों व बेटों को अपनी पत्नी हर्षाना सिंह, मनमोहन कोर पत्नी सतनाम सिंह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उनके द्वारा किए गए कायं के वध वधन जिम्मेदार होंगे। चरनजीत सिंह पुत्र वरु, करनल सिंह, निवासी- 201/6 शास्त्री नगर, काणपुर।

सूचना

मैं HAVLDAR- BENEESH KS S/O P KARUNAKARAN ARMY NO -4007075Y UNIT -4 DOGRA R/o -Vill -Vellarada Post-Kudappanamoodu, Tehsil -Neyyattinkara Distt-Thiruvananthapuram Kerala-695505, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी माता जी का नाम गलती से SOBHY G तथा जन्मतिथि 24-8-1960 लिख गया है जबकि उनका वास्तविक नाम SOBHI G और सही जन्मतिथि 31-8-1955 है इसे दर्ज किया जाए

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्रविक्रम श्री गंगा प्रसाद पुत्र स्त्री श्री पुल्ती व श्रीमती गिरमती पत्नी गंगा प्रसाद की सम्पत्ति: भूखण्ड रक 12 व 12ए स्थित ग्राम तकरोही, वार्ड शरीद भगत सिंह, जगपुर लखनऊ, जिससे संबंधित दस्तावेज मूल बैनाम (Chain Deeds) जो क्रमांक संख्या 3858, दिनांक: 24/06/2005, क्रमांक संख्या: 7108 दिनांक: 18/12/2000 एवं क्रमांक संख्या: 3311, दिनांक: 30/05/2005 पर उपनिर्बंध कायंलय, लखनऊ में पंजीकृत है, जो कि दिनांक 25/07/2024 को मेरे पुत्रविक्रम से गायब / गिर गये हैं। जिस किस्ती को उक्त संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पर कोई आपत्ति/क्लेम है तो नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर आवधिक विधायक को सूचित करें। उपरोक्त समय अवधि के बाद किस्ती को प्रकाश का कोई दावा स्वीकार नहीं माना जाएगा। आपत्ति व विचारक करें। **वीएचओ त्रिपाठी** एडवोकेट पता- सी-135, नरेश विहार, कल्याणपुर, लखनऊ, मो 93-96-7853

इंद्रप्रस्थनगर और पंतनगर में रजिस्ट्री व जायज कागजात वालों को मिलेगा मुआवजा : मुख्यमंत्री

● गलत नीयत से

लाल चिन्ह लगाने वालों की तय होगी जवाबदेही

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ के अकबरनगर इलाके में प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कब्जेदारों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की ओर से पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंत नगर और इंद्रप्रस्थनगर की कार्रवाई को हमने स्थगित करवाया है। एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है

योगी ने कहा, लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए अकबरनगर अब लक्ष्मण जी के नाम पर सौमित्र वन हो गया

और उसके पास जायज कागज हैं तो उसको हम वहां कंपनसेशन देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गरीबों को उनसे बाले जितने भी भूमाफिया हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही थे। साथ ही, सीएम योगी ने भी कहा कि इंद्रप्रस्थनगर और पंत नगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, उन्होंने यह किस नीयत से किया है इसकी पूरी रिपोर्ट दिवाकर रजिस्ट्री की है। अगर किसी ने गलत नीयत से किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिह्नित करने के लिए किया गया है तो यह कुकरैल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए लोगों को सावधान करने के लिए है। सीएम योगी ने लखनऊ से

विधायक रविदास मेहरोत्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आल लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरैल नदी का संगम भी था। अकबरनगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था और यही कारण था कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी टिक नहीं पाया। जिन लोगों को गलत तरीके से पंजी कागजात दिवाकर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेड किया है। अब अकबरनगर कोई नगर नहीं है, बल्कि अब वह सीमित वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भावान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। लखनऊ

उच्च सदन में विरोध स्वरूप वेल में धरने पर बैठ गए नेता प्रतिपक्ष

● सवाल पूछने से रोके जाने का लगाया आरोप, काफ़ी मानमनौत्वल के बाद हुए शांत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधान परिषद में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव अचानक नाराज हो गए और वेल में आकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि उन्हें सवाल पूछने से रोका जा रहा है। सरकार सवाल पूछने में गतिरोध पैदा कर रही है। सभापति मानवंदर सिंह ने उनसे अपनी सीट पर बैठने की अपील की लेकिन वह नहीं उठे। सभापति ने कहा कि पूर्व में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है इसलिए वह अपनी सीट पर जाएं। इस घटनाक्रम के चलते उच्च सदन की कार्रवाई पंद्रह मिनट से अधिक समय तक प्रभावित रही। नेता प्रतिपक्ष का यह विरोध सपा की कार्यस्थान की सूचना पर सवाल खड़े किए जाने पर हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल न पूछने देने का भी

आरोप लगाया। इस दौरान नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष एक-दूसरे को सदन की परम्परा और नियमों का पाठ भी पढ़ाते रहे। शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। सभापति ने उनको बैठने के निर्देश दिए। ऐसा कई बार हुआ तो लाल बिहारी ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं। आप हर बार बैठते हैं। बोलने ही नहीं दिया जा रहा। और वेल में आकर धरने पर बैठ गए। सभापति ने कहा कि कोई भी सवाल नियमों के तहत उठाया जाएगा। लाल बिहारी ने कहा कि ऑनचियल का सवाल वह पूछ रहे हैं। सभापति ने कहा कि ऑनचियल का प्रश्न भी पहले से सूचित किया जाता है। व्यवस्था के प्रश्न पर आप पूछ सकते हैं। लाल बिहारी ने कहा कि अब वह नेता प्रतिपक्ष हैं। सिर्फ सपा के नेता नहीं हैं। शून्य काल में नेता प्रतिपक्ष कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सभापति ने कहा कि नियम के तहत ही पूछ सकते हैं। इस पर लाल बिहारी सभी सपा सदस्यों के साथ वेल में आ गए और धरना देकर बैठ गए। करीब 10 मिनट के गतिरोध के बाद सपा के वरिष्ठ

सदन में अलग अंदाज में नजर आ रहे सीएम योगी

● सपा विधायकों के सवालों पर दिखाया आईना, पूर्व सरकारों पर साधा निशाना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधान सभा के द्वितीय सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। सोमवार को सत्र के पहले दिन जहां कई विधायक उनके पैर छूते नजर आए थे तो वहीं दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने अपने तीखे और व्यंग्य भर लहेजे से विपक्ष के तेवर ही ढीले कर दिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए सपा पर तीखे वार किए और उनके समय की खस्ताहाल व्यवस्था की याद दिलाई तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देने के बहाने उन्होंने शिवपाल यादव और



अखिलेश यादव पर भी व्यंग्य भरे तीर चलाए, जिसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद सीएम योगी के तेवरों में नरमी की उम्मीद कर रहे विपक्षी विधायकों को जोर का झटका लगा। सीएम योगी के तेवर पहले से भी अधिक आक्रामक नजर आए। हालांकि, उनके शब्द व्यंग्य की चासनी में डूबे हुए थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के बहाने सपा के वरिष्ठ

नेता शिवपाल यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपको बधाई, लेकिन आपने भी आखिरकार चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही मार खाता है। सीएम योगी द्वारा मुस्कुराकर दिए गए इस वक्तव्य पर पहले शिवपाल यादव को घेरा में सफाई देनी पड़ी, जबकि दिल्ली में लोकसभा के बाहर अखिलेश यादव भी इस व्यंग्य पर निरुत्तर नजर आए। सीएम योगी ने अपने एक ही तीरे से दोनों को निशब्द कर दिया। इससे पहले, सीएम योगी ने सदन में महिला सुरक्षा को लेकर सपा पर प्रहार किया और यहां तक कह डाला कि महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तो स्वयं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और रसोइयों के मानदेय पर भी उन्होंने सपा को घेरते हुए उससे जुड़े भूमाफिया पर गहवों को उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार ने गोमती नदी और कुकरैल नदी को नाला बना दिया।

उन्होंने लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि लखनऊ से विधायक को आप हैं, लेकिन पैसा सरकार खर्च कर रही है। कुकरैल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है उसके लिए आपको हमारा धन्यवाद कहना चाहिए। सोमवार को सत्र के पहले दिन ही सीएम योगी के प्रति विधायकों की श्रद्धा और आदर देखने को मिला था, जब वह विधानसभा पहुंचे और तमाम विधायक उनके पैर छूने लगे। इसमें सत्तारूढ़ दल के साथ ही कई विपक्षी विधायक भी शामिल रहे। इस दौरान कुंडा से विधायक राजा भीया ने भी सीएम योगी के पैर छूए और उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, पहले दिन वह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से शायरी करने के लिए आग्रह करते भी नजर आए और जब सुरेश खन्ना ने शायरी सुनाई तो सीएम योगी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। उनका ये अंदाज पहले दिन ही चर्चा का विषय बना रहा।

छात्रों से मिलें कुलपति, लें फीडबैक: आनंदीबेन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित समारोह में राजभवन के नवाचारों पर आधारित पुस्तक 'हमारा राजभवन' का विमोचन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अपने कार्य अनुभव व कार्य शैली को साझा करते हुए नियमानुसार एवं दिल से कार्य करते रहने को कहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के विविध कार्यानुभवों को साझा करते हुए कोरोना काल में राजभवन द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की चर्चा की।

राज्यपाल ने गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री के रूप में अपने सफल अनुभवों को भी साझा करते हुए कृषक हित, भू-सुधार, महिला एवं बाल कल्याण के लिए किये गए कार्यों के सफलता के बारे में बताया। कार्यक्रम में आमंत्रित विश्वविद्यालय

● राज्यपाल ने राजभवन उत्तर प्रदेश के नवाचारों पर आधारित पुस्तक 'हमारा राजभवन' का विमोचन किया



के कुलपतियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के निस्तारण की दृष्टि होनी चाहिए इसके लिए कुलपति एवं अधिकारीगण विश्वविद्यालय का निरंतर भ्रमण कर विद्यार्थियों से मिलें और उनका फीडबैक लें, तथा उनकी समस्याओं को निस्तारित करें।

कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय को परिवार की तरह चलाएं और छात्र-छात्राओं को चरित्रशील बनाएं तथा उन्हें लोगों की मदद करने की शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि खुशी कार्य करने तथा कठोर परिश्रम से मिलती है। इसलिए खुश रहें और परिवार एवं बच्चों को

खुशहाल रखें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एवं 'हमारा राजभवन' पुस्तक के संपादक, डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने पुस्तक का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि पुस्तक 'हमारा राजभवन' राज्यपाल उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल के विगत पांच वर्षों की कार्याधि में राजभवन

में हुए नवाचारों एवं नवनिर्माण पर आधारित है तथा इसमें राजभवन को जन-जन का भवन बनाने की प्रवृत्ति तथा विविध गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने राज्यपाल को मातृशक्ति, पितृ शक्ति एवं गुरु शक्ति के रूप में क्षण-प्रतिक्षण देखे जाने की बात की तथा उन्हें दूरदर्शी नेतृत्व, व्यावसायिक सक्षमता, पारदर्शी सुशासन के साथ, सख्त प्रशासक एवं विनम्र एवं सरल स्वभाव के व्यक्तित्व गौरव से सम्पन्न बताते हुए कहा कि वे स्टेट्स वूमन हैं। उन्होंने राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा जगत के स्वर्ण युग की प्रणेता बताया। इस अवसर पर विशेष कार्यार्थिकारी शिक्षा, डॉ. पंकज एल. जानी ने राज्यपाल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों व अभिनव पहलों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्यपाल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से प्रदेश में कई कीर्तिमान बनें तथा शिक्षा

के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिनकी चर्चा पूरे भारत में होती है। कार्यक्रम में राजभवन के अधिकारीगणों में परिसहाय पुनीत द्विवेदी ने राज्यपाल को उदार और विनम्र तथा जन कल्याण हेतु कार्यरत, जन सहभागिता के लिए तत्पर एवं सादा जीवन की मिसाल बताया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी अजय त्रिपाठी ने राज्यपाल को परवाह की प्रतिमूर्ति तथा राजभवन को जन भवन में बदलने की प्रणता बताया। पूर्व सहायक निदेशक सूचना डॉ. सीमा गुप्ता ने राज्यपाल के मार्गदर्शन व प्रेरणा की चर्चा करते हुए बताया कि वे लक्ष्य के प्रति पूरी तन्मयता और शिदत से कार्य करती हैं। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अध्यापक, राजभवन के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने पर राज्यपाल व सीएम ने दी बधाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पेरिस ओलंपिक-2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा (मिक्सड टीम) में प्रख्यात शूटर सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों भारतीय शूटर्स को बधाई दी। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का पहला पदक दिलाया था। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया था। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को गर्वित किया है। इसी क्रम में उन्होंने पेरिस ओलंपिक-2024 में देश के लिए पहला पदक अर्जित करने के लिए भी मनु भाकर को बधाई दी है। मनु भाकर ने एयर

पिस्टल शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया है। राज्यपाल ने कहा कि मनु भाकर का व्यक्तिगत एवं मिश्रित एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतना सभी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और उनकी यह उपलब्धि भारतीय खेल जगत को एक नई दिशा देगी।

मिक्सड टीम की इस जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक-2024 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर देश के प्रख्यात सरबजोत सिंह एवं मनु भाकर को हार्दिक बधाई एवं स्वर्णिम भविष्य हेतु मंगलकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि आप दोनों की इस उपलब्धि से समूचा देश हर्षित एवं गर्वित है। आपकी विजय का यह क्रम ऐसे ही जारी रहे। जय हिंद!

लविवि का तीसरा कैम्पस पिपरसण्ड में बनेगा, भूमि की पैमाइश को लेकर टीम गठित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय का तीसरा कैम्पस पिपरसण्ड में बनेगा। यहां पर विवि का कृषि संकाय खोला जाएगा। जिसके लिए कृषि विभाग की जमीन चिन्हित की गई। पिपरसण्ड में तीसरे कैम्पस को लेकर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने विवि के कुलपति को बधाई दी है।

बोकेटी स्थित सीबी गुप्ता कृषि महाविद्यालय विवि से सम्बद्ध है। ऐसे में विवि के सारे नियम-कानून कृषि महाविद्यालय पर लागू होते हैं। नियमन: जिस विषय का संचालन विवि स्तर पर किया जाता है, उसका अपना एक संकाय होना जरूरी है। ऐसे में विवि स्तर पर कृषि संकाय खोलने को लेकर भूमि के लिए दो वर्ष पूर्व शासन को पत्र लिखा गया था। जिसके तहत बिजनौर के अंतर्गत पिपरसण्ड के पास कृषि विभाग की भूमि को संकाय के लिए चिन्हित किया गया है। एसडीएम सरोजनीनगर के स्तर से जारी आदेश में कृषि विभाग की भूमि के चिन्हिकन को लेकर नायब तहसीलदार गोवर्धन कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी में राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्र, लेखपाल हरस्वरूप, लेखपाल अभिषेक गुप्ता, लेखपाल विश्राम, लेखपाल सर्वजोत सिंह, लेखपाल विशाल यादव, लेखपाल आजाद वर्मा और लेखपाल सुधीर कुमार शर्मा शामिल हैं।

नालियां चोक होने पर अवैध डेरियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राजधानी को स्मार्टसिटी बनाने के लिए शहरी इलाकों में चल रही अवैध डेरियां जिनके संचालकों द्वारा नालियों में गोबर व गन्दगी फेंक कर नालियों को चोक किया जा रहा था जिनकी शिकायत आई जीआरएस लगातार स्थानीय लोगों से मिल रही थी जिस पर नगर आयुक्त के आदेश पर अवैध डेरियों को शहरी क्षेत्र से हटाया गया।

मंगलवार को नगर आयुक्त इंद्रजोत सिंह के आदेश पर अवैध डेरियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पारा क्षेत्र में जोन 6 के विहार, गदीयावा और आस पास क्षेत्र पर नगर निगम ने पुलिस बल, प्रवर्तन दल और कैटल कैमिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाकर 4 गाय, 11 अग्रदूषण कारक पशु मारा गया है जिसके चालते नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

कार्रवाई के दौरान कई अवैध डेरी संचालक पशुओं को लेकर भाग गए। नगर निगम की तरफ से सम्बंधित पुलिस उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा। कार्रवाई के दौरान डेरी संचालकों द्वारा गाली गलौज तथा झड़प भी की गयी। डेरी संचालकों द्वारा टीम का धेराव करने की कोशिश के साथ गाड़ी से पशु उतारने की कोशिश भी की गयीए कुछ जगह पर डेरी संचालक पशुओं को घर के अंदर बंद करके ताला लगाकर भागने लगे। पहले नगर निगम कैटिल कैमिंग टीम के चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी। उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है। नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसूच भैंस को अग्रदूषण कारक पशु माना गया है जिसके चलते नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

जनसुनवाई में कमिश्नर ने अवैध निर्माण पर अवर अभियंता को दिया कारण बताओ नोटिस

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

शहरवासियों की समस्या को मंडलायुक्त द्वारा एलडीए के सभागार में सुना गया। जनसुनवाई में पहुंचे करन सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके द्वारा लालबाग में हो रहे एक अवैध निर्माण पर कई बार लिखित शिकायत की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मंडलायुक्त द्वारा रिपोर्ट तलब कर अवर अभियंता को सो कांज नोटिस जारी की गयी। वहीं, 37 प्रार्थना पत्र में से नौ प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।

एलडीए में मंगलवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नगरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें डीएम सूर्यपाल गंगवार, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पूर्व में नगरिक सुविधा दिवस में प्राप्त हुयी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब से प्रत्येक प्रार्थना पत्र के सापेक्ष



की जाने वाली कार्यवाही के सम्बंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराना होगा। जनता की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है, इसके लिए सतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रकरण का निस्तारण माना जाएगा। प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि आज के नगरिक सुविधा

लालबाग में हो रहे एक अवैध निर्माण के सम्बंध में कई बार लिखित शिकायत की गयी। लेकिन, मामला संज्ञान में होने के बाद भी प्रवर्तन जोन.6 में तैनात अवर अभियंता संजय शुक्ला ने प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे बिज्डक के होसले बुलंद हैं और स्थल पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस पर मण्डलायुक्त ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए अवर अभियंता संजय शुक्ला को शो कांज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया कि वह स्वयं स्थल निरीक्षण करके प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व नगर आयुक्त इंद्रजोत सिंह समेत कई विभागों के संक्षम अधिकारियों द्वारा जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इनके निस्तारण के सम्बंध में सम्बंधित को दिशा-निर्देश दिये गये।

पूर्व सांसद संघमित्रा ने किया सरेंडर अदालत ने अंतरिम जमानत की मंजूरी

● बिना तलाक के दूसरी शादी करने का मामला

विधि संवाददाता। लखनऊ

बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने व मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी तथा साजिश रचने के मामले में एमपीएमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें 12 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने आदेश में कहा है कि इस शर्त पर अंतरिम जमानत मंजूर किया जाता है कि वह 50 हजार रुपए का निजी मुचलका एवं इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करें। तथा तय तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर



आत्मसमर्पण करें। मंगलवार को विशेष कोर्ट के समक्ष संघमित्रा ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। बोते पांच जुलाई को विशेष कोर्ट ने संघमित्रा के साथ ही उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्या को फरार मानते हुए उद्घोषणा का आदेश जारी किया था। विशेष कोर्ट ने यह आदेश दीपक कुमार स्वर्णकार की ओर से दाखिल परिवार पर सुनवाई करते हुए दिया था। विशेष कोर्ट ने इन दोनों के अलावा तीन अन्य अभियुक्त नीरज तिवारी, सूर्य

प्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अदालत ने इन तीनों को भी फरार घोषित किया है। पत्रावली के अनुसार सुरागत गोल्फ सिटी के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत में दाखिल अपने परिवार में आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 से वह एवं संघमित्रा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्या ने उसे बताया था कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है। लिहाजा उसने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर नहीं होने पाए इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया। विशेष अदालत ने अभियुक्तों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं।

बेसमेंट में खुले 20 कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी एलडीए ने की सील

● एलडीए उपाध्यक्ष ने मानक के विपरीत बेसमेंट के निर्माण व संचालन के खिलाफ कार्यवाही के लिए गठित की कमेटी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एलडीए ने शहर में अवैध रूप से बेसमेंट के निर्माण व संचालन के खिलाफ मंगलवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के आदेश पर हरकत में आये प्रवर्तन दस्ते ने अवैध रूप से बने बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 20 प्रतिष्ठानों को बंद कराकर सील कर दिया। भवनों में मानक के विपरीत बने बेसमेंट के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सके, इसके लिए उपाध्यक्ष ने जोन वार अधिकारियों की टीम भी गठित की है, जोकि ऐसे प्रकरणों में लगातार कार्यवाही करती रहेगी। मंगलवार को एलडीए उपाध्यक्ष



प्रथमेश कुमार ने बताया कि मानक के विपरीत बेसमेंट के निर्माण व संचालन से आसपास के भवनों व जानमाल की सुरक्षा को खतरा रहता है। खासतौर से मानसून के मौसम में बेसमेंट के निर्माण में सावधानी न बरतने से खतरों की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए शहर में अवैध रूप से किये जा रहे बेसमेंट के निर्माण व संचालन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में जोन वार टीम गठित की गयी है जोकि मानक विपरीत बने बेसमेंट को चिन्हित करके नियमानुसार कार्यवाही

कर दिया गया। इन कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी के मालिकों से संचालकों से मानचित्र व निर्माण अनुज्ञा आदि से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवर्तन जोन.4 की टीम ने अलीगंज क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सर्वाधिक 7 प्रतिष्ठानों को सील किया। इसमें स्कालर हब लाइब्रेरी, साइलेंस जोन लाइब्रेरी, प्रयास लाइब्रेरी, लक्ष्य लाइब्रेरी स्टार लाइब्रेरी, द स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी और विजन आईएसएस लाइब्रेरी शामिल हैं। यह सभी प्रतिष्ठान मानक के विपरीत निर्मित बेसमेंट में संचालित थे। इसके अलावा प्रवर्तन जोन.1 की टीम ने गोमती नगर के विराज खण्ड में स्थित एलेन कोचिंग सेंटर व गोमती नगर के विभव खण्ड में संचालित एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सील किया। प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने कपूरथला चौराहे के पास भाटिया

कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में संचालित महिन्द्रा कोचिंग की लाइब्रेरी को बंद करवाया। इसी तरह एकेटीयू चौराहे से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवर्तन जोन.4 की टीम ने अलीगंज क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सर्वाधिक 7 प्रतिष्ठानों को सील किया। इसमें स्कालर हब लाइब्रेरी, साइलेंस जोन लाइब्रेरी, प्रयास लाइब्रेरी, लक्ष्य लाइब्रेरी स्टार लाइब्रेरी, द स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी और विजन आईएसएस लाइब्रेरी शामिल हैं। यह सभी प्रतिष्ठान मानक के विपरीत निर्मित बेसमेंट में संचालित थे। इसके अलावा प्रवर्तन जोन.1 की टीम ने गोमती नगर के विराज खण्ड में स्थित एलेन कोचिंग सेंटर व गोमती नगर के विभव खण्ड में संचालित एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सील किया। प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने कपूरथला चौराहे के पास भाटिया

कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में संचालित महिन्द्रा कोचिंग की लाइब्रेरी को बंद करवाया। इसी तरह एकेटीयू चौराहे से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवर्तन जोन.4 की टीम ने अलीगंज क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सर्वाधिक 7 प्रतिष्ठानों को सील किया। इसमें स्कालर हब लाइब्रेरी, साइलेंस जोन लाइब्रेरी, प्रयास लाइब्रेरी, लक्ष्य लाइब्रेरी स्टार लाइब्रेरी, द स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी और विजन आईएसएस लाइब्रेरी शामिल हैं। यह सभी प्रतिष्ठान मानक के विपरीत निर्मित बेसमेंट में संचालित थे। इसके अलावा प्रवर्तन जोन.1 की टीम ने गोमती नगर के विराज खण्ड में स्थित एलेन कोचिंग सेंटर व गोमती नगर के विभव खण्ड में संचालित एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सील किया। प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने कपूरथला चौराहे के पास भाटिया

कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में संचालित महिन्द्रा कोचिंग की लाइब्रेरी को बंद करवाया। इसी तरह एकेटीयू चौराहे से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवर्तन जोन.4 की टीम ने अलीगंज क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सर्वाधिक 7 प्रतिष्ठानों को सील किया। इसमें स्कालर हब लाइब्रेरी, साइलेंस जोन लाइब्रेरी, प्रयास लाइब्रेरी, लक्ष्य लाइब्रेरी स्टार लाइब्रेरी, द स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी और विजन आईएसएस लाइब्रेरी शामिल हैं। यह सभी प्रतिष्ठान मानक के विपरीत निर्मित बेसमेंट में संचालित थे। इसके अलावा प्रवर्तन जोन.1 की टीम ने गोमती नगर के विराज खण्ड में स्थित एलेन कोचिंग सेंटर व गोमती नगर के विभव खण्ड में संचालित एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सील किया। प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने कपूरथला चौराहे के पास भाटिया

पूर्व विधायक इंदल रावत की जमानत अर्जी खारिज

विधि संवाददाता। लखनऊ

बतौर जमानत मिले करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करके हड़पने व जानमाल की धमकी देने के मामले में निरुद्ध पूर्व सपा विधायक इंदल रावत की जमानत अर्जी एमपीएमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। बोते 26 जुलाई को इंदल रावत को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

गया था। इंदल रावत के विरुद्ध राज इंद्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2014 में इंदल रावत ने बटहा सबौली स्थित अपनी जमीन पर छ: मंजिल का निर्माण करने के लिए उससे अनुबंध किया था। उसकी कंपनी ने आरोपी की जमीन पर निर्माण करने के एवज में उसे जमानत राशि के रूप में कुल

दो करोड़ 52 लाख रुपए दिए। बाद में पता चला कि इंदल रावत की उस जमीन पर विवाद है। इस पर उसने जमानत के तौर पर दिए गए अपने रुपए वापस मांगा तो अभियुक्त ने पैसे वापस करने से इनकार करते करते हुए जानमाल की धमकी दी। विशेष कोर्ट ने राजेश की अर्जी पर मुकदमा दर्ज कर बिबेचना करने का आदेश थाना गोमती नगर पुलिस को दिया था।

● संगठन को मजबूत करना व समर्पित कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी बनाना हमारा प्रमुख ध्येय: डॉ. राजेश्वर सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को अपने आशियाना स्थित आवास पर 6 नए ताराशक्ति केंद्र सिलाई सेंटरों का लोकार्पण किया। इन केंद्रों की स्थापना विधायक द्वारा सीएसआर फण्ड के माध्यम से सिलाई-कढ़ाई से सम्बंधित मोटराइज्ड और मैनुअल सिलाई मशीनों, पीको और इंटरलॉकिंग मशीनों प्रदान कर की गयी है। मंगलवार को लोकार्पित किये गये ताराशक्ति केंद्रों का संचालन खरिका प्रथम, खरिका द्वितीय, इब्राहिमपुर प्रथम एवं द्वितीय, शारदानगर द्वितीय तथा विद्यावती द्वितीय वार्ड के भाजपा अध्यक्षों द्वारा किया जायेगा। इससे पहले विधायक द्वारा करीब 1200 सिलाई-कढ़ाई



मशीनें प्रदान कर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 114 ताराशक्ति केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मातृशक्ति को समर्पित तारा शक्ति केंद्र मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज 6 नए केंद्र खुल रहे हैं, इसके लिए सरोजनीनगर की महिलाएं बधाई की पात्र हैं, क्योंकि उनके विश्वास, समर्पण और अथक परिश्रम से यही आज 120 ताराशक्ति केंद्रों की स्थापना और स्कूटर इंडिया चौराहे पर सरोजनीनगर के पहले ताराशक्ति केंद्र आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है। विधायक ने सरोजनी नगर में 200 ताराशक्ति केंद्रों की

स्थापना और उनका सामन बाजार में विक्रवाने के लिए आउटलेट के स्थापना का संकल्प व्यक्त किया। विधायक ने भाजपा संगठन का आधार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की शक्ति है, आज लोकार्पित ताराशक्ति केंद्रों की स्थापना का ध्येय समर्पित कार्यकर्ताओं को सशक्त, स्वावलंबी बनाना है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में कराये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरोजनीनगर में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में विधानसभा में नियम 51 के अंतर्गत सम्बंधित मंत्री से वकालत की मांग की है। विधायक ने आगे जोड़ा कि जून 2022 में

लविवि के तीसरे कैम्पस को भूमि आवंटन पर जताया आभार

सरोजनीनगर विधायक ने पिपरसण्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के तीसरे कैम्पस की स्थापना के लिए भूमि आवंटित होने को अपने सपने को साकार होने का नाम दिया, अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर डॉ. सिंह ने लिखा 'बधाई सरोजनीनगर!' सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के पिपरसण्ड ग्राम पंचायत में लखनऊ विश्वविद्यालय के तीसरे कैम्पस कृषि संकाय की स्थापना की जाएगी। सरोजनीनगर तहसील प्रशासन ने भूमि चिन्हित कर ली है, लखनऊ विश्वविद्यालय के इस नए कैम्पस से युवाओं, विशेष रूप से सरोजनीनगर के छात्र-छात्राओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय का विशेष रूप से आभार, सरोजनीनगर में उच्च शिक्षण-प्रशिक्षण वातावरण निर्माण के मेरे सपने को आपने आकर दिया है! लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन कैम्पस के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु श्रेय योगी आदित्यनाथ एवं जिला प्रशासन का आभार! बता दें की डॉ. राजेश्वर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय को अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कराने के लिए लम्बे समय से प्रयासरत थे, उन्होंने सीएम योगी से विश्वविद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन का अनुरोध भी किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन का प्रस्ताव दिया था और उनसे उसके प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता करने का आग्रह किया था। एससीआर से पूरे क्षेत्र में नियोजित विकास होगा और आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या नहीं होगा। विधायक नेआगे बताया कि सरोजनीनगर के विस्तारित क्षेत्र के विकास के लिए 34 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया मेरी प्राथमिकता शिक्षा है, जब देश आजाद हुआ था तब साक्षरता 18 प्रतिशत थी, महिलओं की साक्षरता मात्र 9 प्रतिशत थी, आज भारत उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

परिवहन निगम की बसों में जल्द उपलब्ध होगी कोरियर व पार्सल सेवा

● उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए किया गया अनुबंध

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



योगी सरकार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोरियर/पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक्स लि. दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 9 सितंबर, 2024 तक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ परिवहन निगम की साधारण व एसी दोनों प्रकार की

बसों में मिलेगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण व एसी बसों को मिलाकर कुल 11000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रोजन में झांसी सम्मिलित हैं जहां ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है। परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन निगम के अधिकारियों को अनुबंध में निहित प्राविधानों का शर्त

प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा मार्ग में यात्री टिकटों के निरीक्षण के साथ लगेज का भी निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि परिचालक द्वारा अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग की जाती है तो दोषी कार्मिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं स्टेशन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालकों/परिचालकों द्वारा निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी ठोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक कराएंगे तथा बुकिंग रसीद भी प्राप्त करेंगे। फर्म द्वारा पार्सल रखने के लिए बसों पर आरक्षित स्थान एवं वजन के अतिरिक्त शेष स्थान निगम के यात्रियों के सामान रखने हेतु रहेगा।

आपदा पीड़ितों का सहारा बनी राज्य सरकार, मदद के लिए खर्च कर रही 175 करोड़

● बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अब तक 156 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



योगी सरकार ने विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए भारी भ्रूक रकम जारी की है। जिलों की मांग पर राज्य आपदा मोचक निधि से यह राशि आवंटित की गयी है। योगी सरकार ने जिलों की मांग पर कुल 175 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गयी। इसमें से 120 करोड़ रुपये की धनराशि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, परिवार को राहत सहायता देने, कृषि निवेश अनुदान समेत अन्य राहत कार्यों के लिए पहले ही जारी कर दी गयी थी। इस मद में योगी सरकार ने 36 करोड़ से अधिक की धनराशि दोबारा जारी की है। इसमें सबसे अधिक 30 करोड़ रुपये लखीमपुर

खीरी को दिए गए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों को हरसंभव मदद के लिए काफी संवेदनशील रहते हैं। साथ ही आपदा प्रस्त इलाकों की खुद मॉनीटरिंग के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं। यही वजह है कि पिछले सात वर्ष में प्रदेश में आपदा के दौरान जनहानि और धनहानि में काफी कमी दर्ज की गयी है। साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि

प्रदान की जा रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न आपदाओं के लिए 175 करोड़ 40 लाख 77 हजार 392 रुपये जारी किये हैं। इसमें 6 जिलों (कासगंज, मेरठ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर और मथुरा) को बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, परिवार को राहत सहायता देने, कृषि निवेश अनुदान समेत अन्य राहत कार्यों के लिए 36 करोड़ 75 लाख 77 हजार 392 रुपये जारी किये गये हैं। इसमें सबसे अधिक धनराशि लखीमपुर खीरी को 30 करोड़, पीलीभीत को 4 करोड़, कासगंज को 1.25 करोड़, कानपुर नगर को एक करोड़, मेरठ को 50 लाख और मथुरा को 77 हजार 392 रुपये जारी किये गये हैं। वहीं इससे पहले इसी मद में योगी सरकार ने 120 करोड़ रुपये जारी किये थे। बता दें कि प्रदेश में मानसून के दस्तक देने से पहले योगी सरकार ने 10 करोड़ रुपये राहत कार्यों की तैयारियों के लिये जारी किये थे।

बेमौसम मारी वर्षा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए 65 लाख

राहत आयुक्त ने बताया कि योगी सरकार ने सांड और नीलगाय के आघात से होने वाली घटनाओं के पीड़ितों के लिए फतेहपुर और पीलीभीत को 54 लाख रुपये जारी किये गये हैं। इसमें फतेहपुर को 30 लाख और पीलीभीत को 24 लाख रुपये गये हैं। इसी तरह मानव जीव दूध के लिए बलरामपुर, प्रतापगढ़ और बिजनौर को 64 लाख जारी किये गये हैं। इनमें बलरामपुर को 28 लाख, प्रतापगढ़ को 12 लाख और बिजनौर को 24 लाख दिये गये हैं। वहीं बेमौसम भारी वर्षा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए बलरामपुर, गोरखपुर और पीलीभीत को 65 लाख दिये गये हैं। इनमें पीलीभीत को 50 लाख, गोरखपुर को 10 लाख व बलरामपुर को 5 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है। इसके अलावा लू प्रकोप के लिए मौरजापुर को 8 लाख और औरंगाबाद को 4 लाख आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, आंधी तूफान के लिए बलरामपुर, प्रतापगढ़ और फर्रुखाबाद को 20 लाख दिये गये हैं। इसमें प्रतापगढ़ को 10 लाख, बलरामपुर व फर्रुखाबाद को 5-5 लाख रुपये दिए गए हैं। आकाशीय बिजली के लिए कुल 3 करोड़ 97 लाख दिये गये हैं। इनमें गोरखपुर को 20 लाख, बांदा को एक करोड़, फर्रुखाबाद को 20 लाख, मऊ को 80 लाख, चंदौली को 24 लाख, महोबा को 75 लाख, गोंडा को 20 लाख, बिजनौर को 8 लाख और चित्रकूट को 50 लाख दिये गये हैं। योगी सरकार ने सर्पदर्श के लिए 2 करोड़ 25 लाख दिये हैं। इनमें बांदा को 1 करोड़, चित्रकूट को 50 लाख और महोबा को 75 लाख दिये हैं। वहीं डूबने से होने वाली मौत के लिए प्रदेश के 16 जिलों को कुल 10 करोड़ 16 लाख दिए गए हैं।

अयोध्या शहर मॉडल सोलर सिटी घोषित

लखनऊ। सौर ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। नीति के अन्तर्गत सोलर सिटी को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है कि जहाँ 05 वर्ष के अंत में पारम्परिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10 प्रतिशत की कमी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। अयोध्या शहर की अनुमानित मांग 198 मेगावाट के अनुसार 10 प्रतिशत लगभग 20 मेगावाट के सौर 24 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट की स्थापना एवं कमिश्निंग का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया है उक्त सौर पावर प्लांट की स्थापना सरयू नदी के समीप ग्राम माझा रामपुर हलवार एवं ग्राम. माझा सरायराय परमाणा हवेली अवध, तहसील सदर जनपद अयोध्या में मैसर्स एनटीपीसी ग्रीन इन्जी लिमिटेड द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से की गयी है।

कानून पाठ्यक्रम में फोरेंसिक अध्ययन को शामिल करने की आवश्यकता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब ने पैरवी के सहयोग से नए भारतीय आपराधिक न्याय कानून, न्याय में नवाचार प्रभाव और चुनौतियाँ विषय पर मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ जी.के गोस्वामी, निदेशक उत्तर प्रदेश फोरेंसिक यूनिवर्सिटी रहे। मुख्य अतिथि ने कानून पाठ्यक्रम में फोरेंसिक अध्ययन को शामिल करने की आवश्यकता और गलत सजा को रोकने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य के उपयोग के महत्व पर बल दिया।



सभी का कार्यक्रम में स्वागत किया। कार्यक्रम में तीन भागों में पैल चर्चा हुई। पहली पैल चर्चा का विषय आपराधिक कानूनों में नवाचार प्रभाव एवं चुनौतियाँ रहा, जिसमें विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डॉ प्रेम कुमार गौतम एवं डॉ मलय पाण्डेय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डॉ राधेश्याम प्रसाद ने अपने विचार प्रस्तुत किए। दूसरी पैल चर्चा में आपराधिक न्याय के क्षेत्र में नए साक्ष्य कानून का परिवर्तनकारी प्रभाव विषय पर चर्चा हुई। जिसमे

विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डॉ विपुल विनोद तथा सत्यप्रकाश राय,अभियोजन विभाग में अपर निदेशक एवं मैक्स लॉ फर्म के मोहमद वली इफ्तिखार ने अपने नवीन विचारों से प्रकाश डाला। अंतिम पैल चर्चा में डिजिटल युग में नए आपराधिक न्याय कानून और मानवाधिकार संरक्षण विषय पर विश्वविद्यालय के विधि विभाग से डॉ अर्पणा सिंह, डॉ मनोज कुमार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डॉ आशीष श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे।

बीबीएयू को यूजीसी से मिला प्रशस्ति पत्र

लखनऊ। बासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज अभियान के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र मिला है। इस अभियान के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. पी. वर्मा के दिशादेशों में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जो विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जुड़े उद्देश्यों में संलग्न करने एवं समग्र विकास के अमूल्य अवसर प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. पी. वर्मा ने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि, यह उपलब्धि समस्त विश्वविद्यालय पर उभरता है। प्रशस्ति पत्र का अर्पण डॉ. अर्पणा सिंह, डॉ मनोज कुमार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डॉ आशीष श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे।

कांग्रेस की नीतियों व विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जाने की जरूरत: अजय राय



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तथा कां प्रकोष्ठ को कार्यक्रम से देश की आम जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को साझा किया है, आज हमें भी अपने नेता के पग चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जाना है और उन्हें कांग्रेस संगठन से जोड़ना है। अजय राय मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बैठक की

अध्यक्षता प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. जियाराम वर्मा ने की। राय ने कहा कि आज देश में किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों को जान चुका है। ऐसे में हमें उनका विश्वास जीतना है और उनके हक हक्क की लड़ाई के लिए आगे बढ़कर संघर्ष करने की आवश्यकता है। बैठक को सम्बोधित करते हुए चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. जियाराम वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से अधिक चिकित्सकों को जोड़कर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच गांव चयनित

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निदेशन में उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पर्यटन विभाग मिलकर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। सोनभद्र में इस तरह की मुहम को जारी रखने के सार्थक प्रयास चल रहे हैं। मिशन अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए जनपद सोनभद्र में पांच गांव का चयन किया गया है, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए अग्रसर किया जा रहा है। प्रथम चरण में सोनभद्र के मऊकला गांव में 6 दिवसीय बास से कई चीजें बनाने का प्रशिक्षण पर्यटन विभाग एवं आजीविका मिशन के द्वारा संचालन से दिया जा रहा है, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बास से बने विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि वह महिलाएं उत्पाद बनाकर के ग्रामीण पर्यटक के रूप में आने वाले पर्यटक को अपने उत्पादों को दिखा सकें एवं बेचकर के अच्छी आमदनी कर सकें।

शहर में बढ़ रहे संक्रामक रोग के मरीज, शिविर में करा रहे इलाज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मोहनलालगंज और मायावती कालोनी, तकरोही में डायरिया के मरीजों के मिलने के बाद शहर में संक्रामक रोग, बुखार, जुकाम और पेट दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बांटे 24 घंटे में इंदौर नगर तकरोही में ही 15 नए मरीजों ने वहां लगे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर इलाज कराया है। वहीं फैजुल्लागंज के डुडौली पीएचसी के तहत 87 मरीजों का इलाज डॉक्टरों ने किया। सीएमओ के मुताबिक इंदौर नगर सीएचसी की टीम ने तकरोही मायावती कालोनी में 242 घरों का सर्वे कर 1273 लोगों की मरीज एंजिडिटी, गैस, अपच और दूसरे मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द के रहे। इन सभी को जरूरी दवाएं निःशुल्क वितरित की गईं। इसके अलावा फैजुल्लागंज के डुडौली पीएचसी के डॉक्टर और स्टाफ ने नौबस्ता में शिविर लगाकर 87 लोगों की मरीजों की। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि न्यूट्राटार मरीज सर्दी, जुकाम, बदन दर्द के रहे। सभी को दवाएं दी गईं। सीएमओ की ओर से दावा यह भी किया गया है कि फैजुल्लागंज के कुणालोक कालोनी में संक्रामक रोग जैसी स्थिति नहीं है। इलाकों में ओआरएस पैकेट, जिंक, पैरासिटामॉल आदि जरूरी दवाओं का वितरण लोगों के बीच किया गया। कालोनी में अंश सिंह, शुभम, अरम, परी, आयुष आदि को बुखार, उल्टी की शिकायत थी। सभी का इलाज जारी है।

श्रीबंदी माता मंदिर में सप्त दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गोमती नदी के तट पर माता सीता के एतिहासिक मंदिर श्रीबंदी माता मंदिर में सप्त दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया गया है। अनुष्ठान में श्री शतचंडी महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, भंडारा, संत सम्मेलन अनवरत चलता रहेगा। श्रीबंदी माता मंदिर डालीगंज के 42वें वार्षिकोत्सव में श्रद्धालुओं की देर रात तक आवाजाही रही। श्री बंदी माता की पूजा,अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मंगलकामनाएं कीं। दिन में यज्ञशाला में स्मृति में हर वर्ष यथा होता है। समारोह में कथा वाचक रोली शास्त्री ने श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर माता सीता ने विश्राम किया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसमें उल्लिखित श्लोक ततो वास मुपागम्य गौतमी तटे आश्रमे पुनारत्थाये गवन्स्य वाल्मीकि आश्रमे इस बात को सिद्ध करता है। जून अखाड़े के उपाध्यक्ष एवं श्रीबंदी माता मंदिर डालीगंज के महंत देवेन्द्र पुरी ने बताया कि गोमती तट पर स्थित बंदी माता मंदिर का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जहां माता सीता ने विश्राम किया था। महंत भास्करानु ने बताया कि सात दिन का वार्षिक समारोह पूर्वज गुरुओं की स्मृति में हर वर्ष यहां होता है। ये सप्त दिवसीय अनुष्ठान

ब्रह्मलीन श्री महंत कपिलेश्वर पुरी जी महाराज एवं सिद्ध संतों की स्मृति में होता है। सात दिन तक प्रतिदिन श्री शतचंडी महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, भंडारा, संत सम्मेलन अनवरत चलता रहेगा। बंदी माता मंदिर डालीगंज के 42वें वार्षिकोत्सव में श्रद्धालुओं की देर रात तक आवाजाही रही। श्री बंदी माता की पूजा,अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मंगलकामनाएं कीं। दिन में यज्ञशाला में स्मृति में हर वर्ष यथा होता है। समारोह में कथा वाचक रोली शास्त्री ने श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। पं नित्यानंद व साथी कलाकारों ने गीतों लिखा गया। वहीं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के अंतर्गत संगीत विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस विभाग के अंतर्गत 1 वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक के संचालन को मान्यता दी गयी। ललित कला विभाग में संचालित एमवीए पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित 32 सीटों के अतिरिक्त 12 सीटों की बढ़ोतरी

पुनर्वास विवि में शुरू होंगे कई कोर्स, संगीत व योग विभाग की होगी स्थापना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में नये सत्र से कई कोर्स शुरू होंगे। साथ ही परिसर में योग व संगीत विभाग की स्थापना की जायेगी। इस बावत मंगलवार को सम्मन हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।



विवि के कुलपति प्रो. संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सबसे पहले योग विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया। वहीं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के अंतर्गत संगीत विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस विभाग के अंतर्गत 1 वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक के संचालन को मान्यता दी गयी। ललित कला विभाग में संचालित एमवीए पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित 32 सीटों के अतिरिक्त 12 सीटों की बढ़ोतरी

के साथ कुल 44 सीटों पर प्रवेश का निर्णय लिया गया। क्रीडा एवं योग प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गयी क्रीडा नीति 2024(स्पोर्ट्स पालिसी) को अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके तहत आगामी सत्र से प्रवेश में 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा को मान्यता दी गयी। बैठक में विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह हेतु भारतीय परिधान (क्रीम कलर का कुर्ता एवं सफ़ेद पैजामा / क्रीम कलर का कुर्ता एवं सफ़ेद सलवार /

हेतु छात्र आचरण एवं अनुशासन नियमावली 2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया। यूजीसी द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को अंगीकृत करते हुए रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल को स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

पांच नए कोर्स शुरू करने पर मुहर

बैठक में भारत सरकार की नियामक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) से पांच नए पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता मिलने के पश्चात अकादमिक काँसिल में अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरिअल बाल्ड थैरेपी, डिप्लोमा इन हियरिंग ऐड एंड इअमोड टेक्नोलॉजी, बैचर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एच.डी नियमावली 2024 को अनुमोदन देने के साथ ही फैकल्टी बोर्ड रेगुलेशन 2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। छात्र अनुशासन

युवती से अश्लीलता कर रेप का प्रयास पुलिस ने दो दिन बाद लिखी एफआईआर

संवाददाता। मोहनलालगंज

धान की रोपाई कर खेत से लौट रही युवती को अकेला पाकर शोहदे ने अश्लीलता कर उसके गुप्तांगों में उंगली डाल दी। पुलिस को सूचना देने पर आरोपी के भाई ने युवती के परिवार को धमका दिया। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत एसीपी से की। लेकिन जांच के बहाने पुलिस दो दिन तक मामले पर पर्दा डाल रही। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहनलालगंज के एक गांव की युवती खेतों में धान की रोपाई कर वापस लौट रही थी। आरोप है कि गांव के अनूप यादव ने युवती से जबरदस्ती अश्लीलता कर रेप की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर उसका चचेरा भाई आ गया। तब जाकर आरोपी युवती को धमकता हुआ वहां से चला गया। यही नहीं 112 नंबर पर सूचना देने के बाद आरोपी के भाई कुलदीप ने पीड़िता के घर पहुंचकर परिवार को खतम करने की धमकी दी। पीड़िता के भाई की शिकायत पर एसीपी ने मोहनलालगंज पुलिस को कार्रवाई के

निर्देश दिए। फिर भी जांच के बहाने पुलिस मामले को दबाए बैठी रही। हालांकि परिवार की पैरवी के बाद दो दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

करंट लगने से छात्र की मौत

संवाददाता। मोहनलालगंज

घर में आराम कर रहे आठवीं के छात्र को फरौटा पंखे से करंट लग गया। परिजनों ने छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मोहनलालगंज के जाबरोली गांव निवासी रमेश शर्मा का बेटा अंश मंगलवार को कुछ तबियत नासाज होने पर स्कूल से छुट्टी लेकर घर आकर लेट गया। इसी बीच उसे फरौटा पंखे से करंट लग गया। जिसकी चपेट में आकर उसकी हालत बिगड़ गई। तभी घर पहुंची मां ने पड़ोसियों को बुलाकर पंखा हटवाकर अंश को सीएचसी पहुंचाया जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल परिजनों ने बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां गंभीर हालत में उसका उपचार चल रहा है।

नौ माह से न्याय के लिए भटक रहे वादकारियों को फिर मिली तारीख

संवाददाता। मोहनलालगंज

नौ माह से न्याय के लिए भटक रहे वादकारियों को एक बार फिर तहसील से तारीख देकर लौटा दिया गया। जिसे लेकर वकीलों और वादकारियों ने गहरी नाराजगी जताकर सीएम से हस्तक्षेप की मांग उठाई है। वादकारियों का आरोप है कि उनके मामले में सुनवाई पूरी किए बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अब अधिकारी सुनवाई से भी कतरा रहे हैं।

मोहनलालगंज तहसील में बंटवारे और हदबदारी समेत अन्य अधिनियम के लगभग 400 मुकदमे नवंबर दिसंबर माह में तत्कालीन

नाराज वादकारियों और वकीलों ने लगाया प्रार्थना पत्र दर्ज करने में दिलचस्पी न लेने का आरोप

एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य ने सुनवाई पूरी किए बिना ही अदम पैरवी में खारिज कर दिए मुकदमे दर्ज करने से तटका रहे हैं। वकीलों और वादकारियों के दबाव में प्रार्थना पत्र दर्ज किए बिना ही एसडीएम प्रार्थना पत्रों पर तारीख लगाकर मुकदमा दर्ज करने से टरका रहे हैं। मंगलवार को भी ऐसे तकरौबन सौ से अधिक

वादकारी न्याय की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वादकारियों के प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अलबत्ता एक बार फिर एसडीएम ने अगले महीने की तारीख देकर उन्हें वापस भेज दिया। वकीलों और वादकारियों का आरोप है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान मानी जाती है। फिर भी तहसील अधिकारी सैकड़ों वादकारियों को न्याय के लिए दौड़ा रहे हैं। एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा ने बताया वादकारियों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। उनके प्रार्थना पत्र दर्ज करने की शुरुआत कर दी गई है। जल्द ही सभी प्रार्थना पत्र दर्ज कर लिए जाएंगे।

जबरन घर में घुसने लगी विद्युत विभाग की टीम, विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा

मोहनलालगंज। मॉनिंग मास रेड के दौरान बिजली विभाग की टीम पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घर में महिलाओं के सोते और नहाते होने का मुद्दा उठाकर महिलाओं ने भी टीम के रवैए को लेकर गहरी नाराजगी जलाई। हालांकि विभाग ने आरोपों को खारिज कर इसे चोरी छिपाने का तरीका बताया। मोहनलालगंज के बलसिंह खेड़ा में मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे बिजली विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। आरोप है कि टीम में शामिल कर्मचारी महिलाओं और बच्चों को बाहर सांता हुआ देखकर भी जबरन घर में घुस गए। आरोप है कि इस दौरान कुछ महिलाएं घर में खान कर रही थी। इसकी भनक लगने पर भी टीम घर में घुसने की कोशिश करने लगी। जिसका ग्रामीणों खासकर महिलाओं ने कड़ा विरोध जताकर हंगामा किया। गांव के अनुज कुमार ने बताया मीटर बदलने के लिए एप्लीकेशन दिए हुए होने के बाद भी टीम में शामिल अधिकारी कुछ भी सुनने से इंकार कर चोरी का झूठ आरोप लगाने लगे। जबकि एक अन्य ग्रामीण का केबिल बंदरों ने तोड़ दिया था। जिस पर टैप लगा था। लेकिन टीम ने टैप उखाड़कर चोरी के आरोप में वीडियो बनाया शुरू कर दिया। विरोध जताने पर टीम में शामिल कर्मचारी नुकसान करने की धमकी देने लगे। हालांकि विरोध के बाद टीम गांव से वापस चली गई। उधर अधिकारियों ने आरोपों को वेबुनियाद बताया।

म्यूचुअल व रिक्त स्थानांतरण का लाभ देने के लिए नीति बनाने पर सहमति



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समस्याओं के निस्तारण को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आंदोलन के लिए प्रदेश भर से बुलाये गये एनएचएम कर्मियों को विधानसभा सत्र होने के चलते रोकने के बावजूद मंगलवार को तकरौबन 5000 की संख्या में संविदा कर्मी एनएचएम कार्यालय पर उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल की मिशन निदेशक से वार्ता की। वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि संविदा कर्मिकों को

म्यूचुअल एवं रिक्त स्थानांतरण का लाभ देने हेतु नीति बनाई जाएगी। आगामी दो माह में पोर्टल खोला जाएगा, जिससे म्यूचुअल ढूँढने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर आवेदन के उपरांत विभाग म्यूचुअल के साथ रिक्त पदों पर स्थानांतरण की विधानसभा सत्र होने के चलते रोकने दूर करने हेतु समिति का गठन कर संगठन के सुझावों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को आगामी दो दिनों में भेजा जाएगा। समस्त संवर्ग को वरीयता दिए जाने हेतु कार्यवाही शासन द्वारा प्रक्रिया में है।

डीएम ने कटेहरी ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण

● अनुपस्थित सविदाकर्मी की सेवा समाप्त करने के निर्देश

संवाददाता। अंबेडकर नगर

जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा विकासखंड कटेहरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में काफी गंदगी पाई गई तथा कार्यालय अस्त-व्यस्त पाया गया। जिस पर नाराज जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई गई। तथा सफाई कर्मी को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि कार्यालय को साफ-सफाई तत्काल करो। पुनः साफ-सफाई में लापरवाही पाई गई तो बर्खास्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित माया पत्नी उदयभान मौर्य की शिकायत सुनी गई।

उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की कि मेरा शौचालय नहीं बना है मैं 2 वर्ष से दौड़ रही हूँ परंतु कोई सुनवाई नहीं की जा रही है जिस पर



जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि इनका तत्काल जांच कराया जाए। यदि पात्र हैं तो तत्काल शौचालय आवंटित किया जाए। खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विकासखंड पर आमजन को जो भी समस्याएं हैं चाहे वह आवास के हो, शौचालय के हो तथा अन्य कोई समस्या है तो उसका जांच उपरांत गुणवत्ता पूर्ण व समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण कराया जाए।

मनरंगेरा रजिस्टर ए डीएमएम रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर का

जायजा लिया गया। मौके पर कृष्णलाल सिंघवा कर्मी अनुपस्थिति पाए गए। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बिना किसी सूचना के अभी तक अनुपस्थिति चल रहे हैं। जिस पर नाराज जिलाधिकारी ने सविदा कर्मी कृष्णलाल की सेवा समाप्त करने के निर्देशित किया।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटेहरी का भी निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी कक्ष ए मेडिसिन कक्ष का जायजा लिया गया। निरीक्षण के

दौरान एक्स-रे रूम में एक्स-रे मशीन खराब पाई गई। जिस पर नाराज जिलाधिकारी ने एम ओ आई सी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इसे तत्काल ठीक कराया जाए। ओपीडी पंजीयन कक्ष में कुल 119 मरीज का पंजीकृत पाया गया। मरीज के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई। पंखा खराब अवस्था में पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल पंखा लगवाया जाए जिससे आने वाले मरीजों को पड़ रही गर्मी से किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

साथ ही साथ एम ओ आई सी को निर्देशित किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने की व्यवस्था मरीजों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था साफसफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मरीजों एवं उनके परिजनों से चिकित्सक द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाय। निरीक्षण के दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ए खंड विकास अधिकारी अनुपम सिंह उपस्थित रहे।

टीबी रोगियों को वितरित किया गया पोषाहार

सोनभद्र। हिण्डालको ग्रामीण विकास विभाग रेनूसागर द्वारा संयुक्त चिकित्सालय अनपरा डिवुलगांज में 20 आर्थिक रूप से कमजोर टी बी रोगियों को चिन्हित कर पोषाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त चिकित्सालय अनपरा के डा० अनुराग गुप्ता, डा० शरद कुमार पाण्डे डा० अनिता यादव व हिण्डालको रेनूसागर ग्रामीण विकास विभाग रेनूसागर के प्रभारी अनिल झा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग के सहप्रबन्धक संजीव श्रीवास्तव ने समस्त टी बी रोगियों का स्वागत करते हुए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टी बी रोगियों के सहयोग हेतु क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर डा० अनुराग गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में टी बी एक सामान्य रोग है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को जो भी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका नियमित सेवन एवं सही खानपान से यह बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है।

केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में हिंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

संवाददाता। प्रयागराज

केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर कार्यालय में मंगलवार को मुख्य राजभाषा अधिकारी संजय सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिंदी निबंध हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा वाक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी संजय सिंह नेगी ने कहा कि राजभाषा हिन्दी का व्यापक प्रचार प्रसार प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री नेगी ने कहा प्रतियोगिता में प्रस्कार प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। उन्होंने कहा कि जो प्रतियोगी इस क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सफल घोषित होते हैं उन्हें अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसलिए सभी प्रतियोगी प्रशंसा के पात्र हैं। श्री



नेगी ने प्रतियोगियों को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर

की प्रतियोगिता में शामिल होकर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का नाम गौरवान्वित करें। प्रतियोगिताओं में कोर मुख्यालय सहित अम्बाला जयपुर चैन्नै तथा सिकरंदराबाद परियोजनाओं के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतियोगिताएं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कल्याण सिंह की देखरेख में आयोजित हुई।

महिलाओं का आत्मविश्वास सशक्त बनाने को किया प्रेरित
प्रयागराज। ऐसे दौर में जहां फैशन के प्रति जागरूक लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने स्टायल के लिए लोगों की टिप्पणियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। फैशन एडिटरवियर ने सोनम बाबा के साथ आनन नवीनतम ब्रंड फैशन यू को लॉन्च किया है। इस ब्रंड फैशन का उद्देश्य है महिलाओं को अपने व्यक्तिगत स्टायल को आत्मविश्वास से अपनाने और अपनी फैशन आइडल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना। फैशन एडिटरवियर लिमिटेड की सीएमओ प्रिया अग्रवाल ने इस ब्रंड फैशन के बारे में बात करते हुए कहा कि फैशन भारत में महिलाओं के फुटवियर को देखने के ढंग को बदलने के अभियान पर है। सोनम बाबा के जीवन व्यक्तित्व को महिलाओं के लिए हमारे कलेक्शन के साथ जोड़ने के पीछे हमारा लक्ष्य है। महिलाओं को अनावश्यक टिप्पणियों को दूर करने और हर कदम पर आत्मविश्वास और शक्त महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। यह पहल फैशन के क्षेत्र में सांस्कृतिक बदलाव को प्रोत्साहित करती है।

न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले वृद्ध याची पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित जिला जजों अन्य जजों पर अन्याय आरोप लगा पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने वाले कानपुर नगर के 77 वर्षीय याची रणधीर कुमार पाण्डेय की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए अवमानना कार्रवाई करने के बजाय उनपर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया है और यह राशि उन्हें महानिबंधक के समक्ष 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जमा न करने पर जिलाधिकारी को सूचित किया जाए ताकि वह वसूली कर राशि जमा कराएं। यह राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा होगी। कोर्ट ने अपने आदेश को सही माना और पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रणधीर कुमार पाण्डेय की अर्जी पर दिया है। मालूम हो कि याची 1950 से किरायेदार है। मकान मालिक पुरुषोत्तम दास महेश्वरी और याची के बीच किराएदारी विवाद दाखिल हुआ। जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपील खारिज हो गई तो याचिका दायर की गई। केस रिमांड कर दिया गया। अपील फिर से खारिज कर दी गई तो याचिका दायर की गई। बहस के दौरान याची के वरिष्ठ वकील और कनिष्ठ वकील द्वारा मेरिट पर लड़ने के बजाय विवादित स्थल एक साल में खाली करने का समय मांगे जाने पर याचिका निस्तारित कर दी गई। इसके बाद याची ने यह पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर अपने वकीलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये कहा वकील द्वारा मकान खाली करने का बयान उनके कहने पर नहीं दिया गया है। अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। कोर्ट को बताया गया कि अपील पर भी जिला जज व अन्य जजों पर याची ने गंभीर आरोप लगाये हैं और अदालत को बदनाम करने का प्रयास किया है। एक वरिष्ठ वकील ने कहा याची के दुराचरण के कारण उन्होंने केस लड़ने से स्वयं को अलग कर लिया था।

प्रयागराज। प्रयागराज पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय सोरों में नामांकन मेला एवं प्रवेशोत्सव आज सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत बच्चों द्वारा गाकर किया। ग्राम पंचायत सोरों में निवास करने वाले वनवासी जाति के कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर नामांकन कराया गया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अपने हाथों से नामांकन किया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है। जिसकी पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग तक बचके तक सरल एवं सुलभ हो विभाग एवं शासन को ऐसी ही मंशा है। जिसको धरातल पर उतारने का पुनीत कार्य पीएम श्री उच्च

बीएसए ने वनवासी बच्चों का विद्यालय में किया प्रवेश

संवाददाता। प्रयागराज

प्रयागराज। प्रयागराज पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय सोरों में नामांकन मेला एवं प्रवेशोत्सव आज सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत बच्चों द्वारा गाकर किया। ग्राम पंचायत सोरों में निवास करने वाले वनवासी जाति के कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर नामांकन कराया गया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अपने हाथों से नामांकन किया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है। जिसकी पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग तक बचके तक सरल एवं सुलभ हो विभाग एवं शासन को ऐसी ही मंशा है। जिसको धरातल पर उतारने का पुनीत कार्य पीएम श्री उच्च



प्राथमिक विद्यालय सोरों के अध्यापकों एवं मैथिली ग्रीव कल्याण समिति के सदस्यों ने मिलकर किया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी एवं बीओ प्रतापपुर विश्वनाथ प्रजापति बीओ फूलपुर प्रभाशंकर पांडेय ग्राम प्रधानपति राजित राम यादव बच्चों को पुस्तकों का सेट यूनिफॉर्म बैग कला कलम वितरित किया गया। प्रधानाध्यापक अजीत प्रताप सिंह एवं उनकी टीम ने मुख्य अतिथि बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि को बुके अंगवस्त्रम एवं स्मृतिचिह्न भेंट किया। मैथिली ग्रीव कल्याण

समिति के पदाधिकारी बालकेश्वर प्रजापति रमेश सरोज संदीप एवं राजेश सरोज और अन्य सदस्यों को भी बुके अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। संचालन वरिष्ठ एआरपी सत्येन्द्र द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम से पूर्व बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बीओ प्रतापपुर एवं मैथिली ग्रीव कल्याण समिति के सदस्य और प्रधानाध्यापक वनवासी बस्ती में स्वयं जाकर बच्चों एवं अभिभावकों से मिलकर शिक्षा एवं स्कूल चलो अभियान के प्रति जागरूक किया। साथ ही अपने समक्ष बच्चों के बाल भी कटवाए

एवं उन्हें स्वच्छता स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद पांडेय ब्लॉक अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ब्लॉक मंत्री दिलीप कुमार यादव ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ प्रतापपुर डॉ हरीशचंद्र मंत्री अतीक अहमद टीएससीटी प्रदेश मरामंत्री जिले से वरिष्ठ एआरपी जय सिंह शशिकांत सुदेश पांडे रविराज तिवारी पूर्व समन्वयक दिनेश यादव ब्लॉक स्काउट मास्टर अमरेंद्र कुमार एवं ब्लॉक के समस्त शिक्षक संकुल शिक्षक एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

डीएवी पब्लिक स्कूल में मतदान के द्वारा विद्यार्थी परिषद का हुआ गठन

संवाददाता। बीजपुर, सोनभद्र

डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी रिहंदनगर में विद्यार्थी परिषद का गठन लोकात्मिक पद्धति से मतदान के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार ने विद्यार्थी परिषद के चुनाव में चुनाव आयुक्त की भूमिका का निर्वहन करते हुए बताया कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन पद्धति नहीं है; बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। यह मानव के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लोकात्मिक मूल्यों से विद्यार्थियों में समानता के भाव का संचार होगा। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल लोकतंत्र का आधार है। विद्यार्थियों ने इस चुनाव के माध्यम से सीखा कि लोकतंत्र में बहुमत से जीत होती है। चुनावी प्रक्रिया में सर्वप्रथम बारहवीं कक्षा के चार विद्यार्थियों ने हेड ब्याज पद के



लिए शिवम सिंह और सौरभ सिंह तथा हेड गर्ल पद के लिए इशिता सिंह एवं दीक्षा दूबे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार ने चारों नामांकन पत्रों को वैध ठहराते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। बैलेट पेपर के माध्यम से कक्षा आठवीं से बारहवीं तक के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य राजकुमार के साथ सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अनन्त मोहन सीएसए कॉर्डिनेटर प्रभा सिंह प्रेमलता शर्मा शबनम अरुण कुमार सिंह प्रियंका दुबे की उपस्थिति में गुप्त मतदान किया। मतदान के दौरान चारों प्रत्याशी मौजूद रहे।

मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। सभी विद्यार्थियों में पहली बार मतदान में हिस्सा लेने के लिए उत्साह देखा गया। बैलेट पेपर की गिनती का काम डॉ राजेश कुमार श्रीवास्तव प्रभा सिंह प्रेमलता अरुण कुमार सिंह एवं प्रियंका दुबे ने मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में किया। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले सौरभ सिंह को हेड ब्याज और शिवम सिंह को डिप्टी हेड ब्याज के पद पर तथा हेड गर्ल के पद पर दीक्षा दूबे और डिप्टी हेड गर्ल पद पर इशिता सिंह को विजयी घोषित किया गया।

किसानों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता होगी जरूरी

प्रयागराज। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के प्रभाग श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स ने फसलों की सुरक्षा एवं उन्हें पोषण प्रदान करने वाले चार नए क्रॉप प्रोटेक्शन एवं स्पेशली प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लांच किए हैं। लांच कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। जहां क्षेत्र के मुख्य चैनल पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं दो सी अस्सी से अधिक वितरकों और पांच हजार से अधिक किसानों ने भी लांच कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्रीराम सुपर क्लैंट सीड गेहूंसव योजना के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी हुआ। जहां उत्तर प्रदेश से एक सौ 88 विजेताओं को सम्मानित किया गया। संजय छाबड़ा एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर एवं बिजनेस हेड ने कहा कि यह पांच प्रोडक्ट्स आधुनिक समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो किसानों की बदलती जरूरतों को पूरा कर स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।

आर्य कन्या इंटर कालेज में हुआ छात्र परिषद का गठन



प्रयागराज। आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुट्टीगंज के प्रबंधक पंकज जायसवाल के संरक्षण एवं प्रधानाचार्या अर्चना जायसवाल के दिशा निर्देशन में छात्र परिषद का मंगलवार को गठन किया गया। कक्षा 11 एवं 12 की छात्राओं का बैज अलंकरण कर उनको उनके कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान सुटि शर्मा को विद्यालय का कैप्टेन जिंजासा को वाइस कैप्टेन नियुक्त किया गया। छात्र परिषद का कार्य विद्यालय में अनुशासनात्मक कार्यों के अतिरिक्त छात्र छात्राओं को यथासंभव सुविधा सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना है। छात्र परिषद की सभी

छात्राओं को शपथ दिलाई गई कि वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी एवं कर्मठता के साथ करेगी तथा अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगी। विद्यालय के प्रबंधक पंकज जायसवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र परिषद केवल छात्र संगठन नहीं बल्कि यह देश का उज्जवल भविष्य है। आज के युवाओं के चरित्र निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि यह घने अंधेरे में आती रोशनी की किरण है। विद्यालय की सभी छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देंगी।

अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग को लेकर आम आमी पार्टी ने किया प्रदर्शन

संवाददाता। मीरजापुर

आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज जिला मुख्यालय मिर्जापुर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर प्रत्याहित करने एवं उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन एवं आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र महामंत्री राष्ट्रपति महोदय को संबोधित मिर्जापुर जनपद के जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन को सौंपा।



देवी प्रसाद चौधरी पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंदू पूर्व मंत्री गुलाबचंद यादव मुन्शी आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे एडवोकेट माले की नेता मोहम्मद सलीम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दामोदर मौर्य एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित शुक्ला लखू द्वारा मंडलीय चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर में व्यास दुर्घटना एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मिर्जापुर में व्यास भ्रष्टाचार पर और जनपद को

सूत्राग्रस्त घोषित करने एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य ईमानदारी से करने की मांग पर भी वार्ता किया। जिस पर जिलाधिकारी मिर्जापुर में तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी का डेलिगेशन अपर आयुक्त डॉ विश्राम से कमिश्नरी में मिलकर उनको भी ज्ञापन पत्र सौंपा गया आज इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जन

अधिकार पार्टी, सीपीआई, माले के सैकड़ों कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय पर उपस्थित होकर इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ किया जा रहे व्यवहार तथा व्यवहार को घोर निंदा करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र को समाप्त करने का कार्य कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल में बंद कर दिया गया है और जेल में भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिसकी घोर निंदा की जाती है केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही खत्म करना चाहते हैं।

अभियान चलाकर ओवरलोड गाड़ियों की कटायी जाये जांच: जिलाधिकारी

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी०एन० सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी बैठकी की गयी, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु जनमानस को जागरूक किया जाये और दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र को सड़कों को गढ़वा मुक्त करते हुए सड़कों को मरम्मत की जाये। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों व बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले की जांच एआरटीओ, पुलिस विभाग आपस में सम्मन्य स्थापित करके अभियान चलायें, उन्होंने टोल प्लाजा से होकर जाने वाली सड़कों के ग्राहू को गढ़वा मुक्त किया जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, उन्होंने कहा कि राबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद में स्थित ओवरलोड के नीचे खाली पड़े स्थानों पर सौन्दर्यीकरण हेतु क्या कार्य किये जा सकते हैं, उसके सम्बन्ध में कार्ययोजना

बनायी जाये, जिससे कि क्षेत्र स्वच्छ और सुन्दर दिखें, जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को सड़कों को मरम्मत और सड़कों के किनारे साईनेज बोर्ड लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बेहतर ईलाज मिल सके और उसका जीवन सुरक्षित हो सके। इसके लिए बेहतर कार्ययोजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनायी जाये और एम्बुलेंस को संख्या को बढ़ाया जाये, उन्होंने ए०आर०टी०ओ० को निर्देशित करते हुए कहा कि गाड़ियों का फिटनेस की जांच समय समय पर की जाये। और ड्राइवरों के आंखों की जांच हेतु कैम्प लगवाया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालय में संचालित होने वाली वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाये और ड्राइवर और कन्डेक्टर की आंखों का परीक्षण भी कराया जाये।

विक न्यूज

डीएम ने डीवीएम गोदाम व कार्यालयों का किया निरीक्षण

गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी अर्चना अश्वरी ने मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित इंडीगोएम गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय स्थित गोदाम में परेशा हेतु एक दार खोले जाने एक अन्य परेशा दार को बन्द किये जाने और इंडीगोएम गोदाम के परिसर में साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया। इंडीगोएम सुखा में तैनात गाईस में 1 सुरक्षा गार्ड अनुपस्थित पाया गया, अनुपस्थित कार्मिक के संबंध में पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते जाने के निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/ज्य जिला निर्वाचन अधिकारी को लागूये गये लीट प्रोत्साहित करना के रिहाइजा की जांच करवा का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अर्चना अश्वरी ने तहसील जखनिया के विभिन्न पटलों का मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय, उपजिलाधिकारी न्यायालय कथ, नायब तहसीलदार कथ, न्यायालय तसीलदार कथ, नाजीर कथ, राजस्व लिपिक, राजस्व निरीक्षक कथ, अभिलेखागार, सहाय कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पटलों पर कार्य संचालन रूढ़ एवं कुछ पटलों पर कतिपय तिली निसे दुस्सह करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान ए डब्ल्यू बी एन अशोक कुमार से फाइलों के बेतरतीब ढंग से रख रखाव एवं कार्यालय रजिस्टर अपडेट न होने पर सार्विकरण मांगा गया।



राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को

सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश लेखेन्द्र यादव की अध्यक्षता में लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में जनपद न्यायालय के एडीओआर मनन के विश्राम कथ में बैठक की गयी, बैठक के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश लेखेन्द्र यादव ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षलुण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा 14 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं वाढ न्यायालय ओबरा एवं दुई के प्राणम में तथा घोरावल एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत का आयोजन सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना है, उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर प्रभावी तैयारी कर लें,उन्होंने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक उपयुक्त प्रकरणों के निस्तारित करने का निर्देश दिया गया, इस निमित्त उनके अपेक्षा की गयी कि वे समस्त प्रशासनिक विभागों व अनुभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें। बैठक में आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन अधिकारी आर०पी० गौतम श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी०सी० मनमोहन एवं प्रभारी जिला सूचना अधिकारी सुभाषु शेखर शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।

लोगों को समझाने पर दिया गया व्यापक जोर

प्रयागराज। देरा में सैटेलाइट टेलीविजन का अगामी जी टीवी 1992 में अपनी शुरुआत से ही टीवी जनत में नए मुकाम हासिल करने में सबसे आगे रह है। हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जीईसी के रूप में जी टीवी ने हमारे ऐसी अनोखी कल्पितियों से आने लोगों को आकर्षित किया। जो उनकी स्वाईड बना करती है। उनके दिलों को छू जाती है और उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरती है। इस समय जब मीडिया और मनोरंजन एक रोमांचक मुकाम पर है। वहीं सब लोगों को समझने पर पहले से ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। इसी कड़ी में इसने एक बेड इंफान्टार आल न्यूकान की शुरुआत की है और दर्शकों की पसंद में आने वाली है। अहमिगत समझी है। चैनल ने हमारा परिवार नाम की एक अनोखी पहल प्रस्तुत की है जो कि उत्साही टीवी दर्शकों का एक नया परिवार है। अपने जो और किस्मों के बारे में रिपल टाइन दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुन है। पिछले चार हफ्तों से हमारा परिवार को लेकर चर्चा जोरों पर है।

डीएम ने डीवीएम व वीवी पेट गोदाम का किया निरीक्षण

सोनभद्र। जिलाधिकारी बीज सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित डीवीएम व वीवी पेट गोदाम का मासिक निरीक्षण किया, इस दौरान गोदाम की सुरक्षा के साथ ही आवश्यक व्यवस्था का जरूरा लिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के



निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा मासिक निरीक्षण किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाता है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में लगे सीसीटीवी के माध्यम से बारी बारी से डीवीएम व पीपी पेट के कक्षों की स्थिति का जांचना लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था में तत्ते सुरक्षा बलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि गोदाम परिसर के आस-पास के झण्डियों का गठान व साफ सफाई भी करा ली जाये। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी न्यायालय सचिव पटेल, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।

ग्रीनफील्ड पर करया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम

गाजीपुर। जनपद में मंगलवार को रवि इंद्र बिल्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (कस्टमर का पोस्टलन हब्री ग (ग्रीन फील्ड) एन एच 31 पैकेज 1 (स्वीडियापुर किमी 0.00 से शाहपुर किमी 42.500 ई पी सी नोड उतर पेट्ट) के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम (एक पेड़ मां के नाम) सी एच 2250 पर करया गया। जिसने नेशनल हब्री अग्रीस्टी ऑफ इंडिया पी आई यू आननभद्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीप्रकाश पाठक, व नैनेजर (टी) नरेन्द्र जी, रवि इंद्र कर्णवी के डायरेक्टर दिलीप सिंह राव, एच अभिषेक सिंह राव, जनरल मैनेजर नरेन्द्र कुमार नगर, प्रोजेक्ट मैनेजर (एच) कापेश्वर राम निपाटी, प्रशासनिक एवं मानव संसाधन विभाग के नवीन चंद्र राव, ऋगुराज सिंह, अर्जुन कुमार, जयदेवराज अंशु एवं कर्णवी के सम्बन्धित कर्णवी मौजूद थे।



योजनाओं की समीक्षा कर डीएम ने दिये निर्देश

अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना गाजीपुर तथा मुख्यमंत्री आवास योजना गाजीपुर की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा लखित वरीकृत आवसों की समीक्षा करते हुए पूर्ण-अपूर्ण आवस, लखित आवस और जीओ टैगिंग के कार्य की विस्तार से जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग कर सभी लखित आवस निर्माण को आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मोदी का भाषण

पाकिस्तान को चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को कठोर चेतावनी दी है, लेकिन इसके बावजूद सीमापार से आतंकवाद लगातार जारी है। चेतावनियों, सेना की उपस्थिति तथा राजनयिक प्रयासों के बावजूद सीमापार से आतंकवाद कटु यथार्थ है। यह हम सबके लिए गंभीर चिन्ता का विषय होना चाहिए कि भारतीय सेना ने इस महीने अपना बारहवां सैनिक खोया है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावग्रस्त संबंध और खराब हो गए हैं। पाकिस्तानी 'बार्डर एक्शन टीम'-बैट द्वारा बिना उकसावे के भारत की अग्रिम चौकी पर फायरिंग के दौरान राइफलमैन मोहित राठौड़ व एक मेजर शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य सैनिक घायल हुए। भारतीय सैनिक उत्तरी कश्मीर के माछिल सेक्टर में एलओसी पार करने का प्रयास करने वाले आतंकीयों के खिलाफ आपरेशन चला रहे थे। 'बैट' में शामिल पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अक्सर एलओसी पार करने वाले घुसपैठियों की सहायता के लिए कवर फायर देते हैं। इस नवीनतम हमले में पाकिस्तानी सैनिकों ने खराब मौसम और कम दृश्यमानता का लाभ उठा कर सैनिक चौकी पर ग्रेनेडों से हमले के साथ गोलीबारी की। लंबे समय तक चली गोलीबारी में दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें से एक बाद में शहीद हो गए। आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है तथा सरकार द्वारा बीएसएफ की दो अतिरिक्त बटालियों ने तैनात करने के बाद इस केन्द्रशासित क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में 2,000 की वृद्धि हुई है। हालिया हमला भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की कठोर चेतावनी के एक दिन बाद हुआ है।



'कारगिल विजय दिवस' पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को कठोर चेतावनी देते हुए जोर दिया कि 'आतंक के आकाओं के बुरे इरादे कभी सफल नहीं होंगे और भारत आतंकवाद की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।' यह कठोर चेतावनी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में वृद्धि के बीच आई है जिसमें तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर घातक हमला शामिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की चेतावनी का आतंकीयों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। नियंत्रण रेखा-एलओसी पर जारी झड़पों तथा जम्मू कश्मीर में बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं के कारण हताहतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उपद्रवादी समूहों को पाकिस्तान का लगातार समर्थन समस्या का कारण है। ऐसे में भारत को समग्र रणनीति बना कर ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगानी तथा सीमा सुरक्षा के साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वास्तव में, दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए यह काम आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें आतंकवाद से मुकाबले की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए ऐसी हर घटना का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों व खासकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान को अलग-थलग करने के साथ ही हमें अपना पक्ष सभी प्रमाणों के साथ रखना चाहिए। अब तक उकसावों के बावजूद भारत जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। सरकार के दृष्टिकोण में विकास पहलें, ढांचागत संरचनाओं में निवेश तथा शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों से संपर्क शामिल होनी चाहिए। आतंकीयों से ज्यादा शक्ति और हाईटेक संसाधनों का प्रयोग कर निपटना होगा। सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और हमें क्षेत्र में शांति व स्थायित्व के लिए कठोर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहिए। सीमापार से आतंकवाद के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की नीति पर चलते हुए हमें अपनी सीमाओं और जनता की सुरक्षा करनी होगी।

बीआरएस पर अस्तित्व का संकट

पार्टी के पास काफी पैसा होने के बावजूद बीआरएस के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। आंतरिक मतभेदों तथा घटते समर्थन के कारण स्थिति और गंभीर हुई है।



कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पार्टी के पास काफी पैसा होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र समिति-बीआरएस के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। आंतरिक मतभेदों तथा घटते समर्थन के कारण उसकी स्थिति और गंभीर हुई है। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति-टीआरएस के नाम से गठित पार्टी ने बाद में अखिल भारतीय पार्टी बनने के उद्देश्य से अपना नाम बदल कर भारतीय राष्ट्र समिति-बीआरएस कर लिया था। लेकिन वर्तमान समय में उसकी गिनती उन राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गई है जिनका असर तेजी से घट रहा है। महत्वाकांक्षी नेता के. चंद्रशेखर राव-केसीआर द्वारा गठित इस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। इसके साथ ही वह हालिया विधानसभा चुनाव में अपने मूल प्रदेश तेलंगाना में सत्ता में बने रहने में भी विफल रही है।

हालांकि, यह स्थिति अनेक अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी है। ये पार्टियां और उनके नेता अधिकांशतः अपने राज्यों में सत्ता पाने में विफल रहे और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका असर लगभग समाप्त हो गया। बीआरएस के पतन की शुरुआत लोकसभा चुनाव से हुई जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। उसे लगा यह झटका अचानक और बहुत तगड़ा था। हालांकि 'पार्टी फंड' में लगभग 1000 करोड़ रुपये थे, लेकिन इसके बावजूद केसीआर के राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की विस्तार की उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदल कर 2022 में बीआरएस कर लिया। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से तेलंगाना हटा कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की इच्छा से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उसकी शाखाएँ खोलीं, लेकिन अब ये इकाइयाँ बंद हो गई हैं।

बीआरएस से जुड़ी यह परिघटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि राजनीतिक परिदृश्य अचानक कैसे बदल जाता है। तेलंगाना में 2023



विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस पिछले दस साल बहुत चुरी स्थिति में रही, जबकि अब वह राज्य की सत्ता में वापस आ गई है। अब बीआरएस को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद अब पहली बार बीआरएस का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लगभग दो दशकों तक तेलंगाना की राजनीति में वर्चस्व स्थापित कर चुकी पार्टी राज्य में लगभग एक दशक तक सत्ता में रही, पर लोकसभा चुनाव 2024 में उसका एकदम सफाया हो गया। बीआरएस के कई नेता पार्टी छोड़ कर तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

पिछले सप्ताह ही बीआरएस को उस समय एक धक्का और लगा जब बीआरएस विधायक ए. गांधी पाला बदल कर सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे बीआरएस के पतन का पता चलता है। तेलंगाना में वर्तमान समय में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास 75 विधायक हैं जिनमें 65 कांग्रेस से, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-भाकपा से और 9 पूर्व बीआरएस सदस्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 2001 में केसीआर ने तेलंगू देशम पार्टी-टीडीपी से इस्तीफा देने का ऐतिहासिक निर्णय किया था। उनका विश्वास था कि केवल अलग राज्य के गठन से ही तेलंगाना क्षेत्र के प्रति भेदभाव समाप्त किया जा सकता है जो मूल आंध्र प्रदेश में उसके प्रति व्याप्त था।

अपनी इस सोच के कारण के. चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के विभाजन और अलग तेलंगाना गठन की मांग की। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में लंबा आंदोलन भी किया। टीआरएस का गठन अलग तेलंगाना प्राप्त करने के लिए किया गया था जो उस समय एक असंभव क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा लगता था। उस समय उनकी आयु 47 वर्ष थी। उस समय टीडीपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2004 में टीआरएस कांग्रेस के साथ चली गई और उसने लोकसभा की पांच सीटों पर विजय पाई।

इसके बाद केसीआर को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-संप्रग सरकार में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी मिली। संप्रग सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह कर रहे थे। लेकिन अलग तेलंगाना राज्य के लिए केसीआर ने संसद के भीतर और बाहर अनेक संघर्ष जारी रखे। 2009 में उन्होंने संसद में 'तेलंगाना विधेयक' पेश करने या अलग तेलंगाना गठन के लिए भूख हड़ताल शुरू की। कुछ दिनों के बाद केन्द्र सरकार ने उनकी मांगों मान लीं। 2014 में होने वाले आम चुनाव के कुछ दिन पहले संप्रग सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य गठन की घोषणा कर दी। इसके बाद टीआरएस ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। उसने लोकसभा में 11 सीटें जीतीं

जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उसने राज्य में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में केसीआर ने राज्य की जनता को खुश करने के लिए अनेक नीतियां लागू कीं। लेकिन इसके बावजूद 2023 के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस से पराजित हो गई।

इसके बाद 9 दिसंबर, 2022 को टीआरएस का नाम आधिकारिक रूप से बदल कर बीआरएस कर दिया गया। इसके साथ ही केसीआर की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ स्पष्ट हो गईं। उन्होंने शुरुआती दौर में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयास किया और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल आदि नेताओं से बार-बार मुलाकातें कीं। लेकिन उनके इन प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला और वे बाद में बने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से बाहर रहे। अब बीआरएस राज्य से एक भी लोकसभा सीट जीतने में विफल रहा है और उसका मत प्रतिशत घट कर 16.69 प्रतिशत रह गया है।

स्पष्ट है कि अब पार्टी अस्तित्व पर संकट का सामना कर रही है। पिछले साल बीआरएस को राज्य में सत्ता से हाथ धोना पड़ा और उसके केवल 35 विधायक बने। बीआरएस प्रमुख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह दूसरे राज्यों में उम्मीदवार उतारने में

विफल रही। केसीआर ने महत्वपूर्ण पद अपने बेटे, भतीजे और बेटों को सौंप कर 'वंशवादी' राजनीति का प्रयास किया, लेकिन इससे विवाद और गंभीर हो गया। इसे पार्टी के मूल सिद्धान्त के विपरीत तथा स्वैच्छाचारिता बढ़ाने का संकेत माना गया। अनेक अन्य तानाशाहों की तरह केसीआर भी नेतृत्व की दूसरी पंक्ति तैयार करने में विफल रहे, जबकि वे केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने वाले नेताओं को छोड़ कर बाकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से सत्ता तक पहुंचे केसीआर धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन से अलग हट गए। उन तक पहुंच आसान नहीं थी और वे मीडिया को संसद नहीं करते थे। इस कारण उनके तथा अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क समाप्त हो गया। केसीआर ने स्वयं को ऐसे लोगों से घिरे दिया जो महत्वहीन थे तथा केवल उनकी चाटुकारिता करते थे। इसके परिणामस्वरूप वे यथार्थ समझ नहीं सके और चाटुकार उनके समक्ष गलत तथ्य रखते रहे। जहां चंद्रबाबू नायडू को कम्पा समुदाय का समर्थन प्राप्त था, वहीं केसीआर को छोटे से वेलाम्मा समुदाय के अलावा और किसी का समर्थन नहीं प्राप्त था। यह राजनीतिक अलगवण केसीआर के पतन का एक प्रमुख कारण था। इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप थे। उनकी बेटी कविता अब 'दिल्ली शराब घोटाले' में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। इसके अलावा राज्य पर ध्यान देने के बजाय केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में उलझने लगे तथा खुलेआम प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से विपक्ष शासित राज्यों के प्रति करने लगे, लेकिन वे विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप बीआरएस 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में विफल रहे। उनको विश्वास था कि उनकी पार्टी अजेय है और वे अनेक अन्य तानाशाहों की तरह तेलंगाना पर अनंत काल तक शासन करते रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए केसीआर ने पालाबदल को बढ़ावा दिया।

अब केसीआर ने सत्ता में शामिल हो गए हैं जो एक समय प्रभावशाली थे, लेकिन अब संघर्ष कर रहे हैं। इनमें शद पवार, लालू यादव, पत्कनीस्वामी, देवेगौडा, मायावती उद्धव ठाकरे व अन्य शामिल हैं। इस प्रकार राजनीति 'सांप सिद्धी' के एक खेल की तरह है।

समावेशीयता व प्रगति पर जनसंख्या का प्रभाव

“
चूंकि विश्व की जनसंख्या 8 अरब के करीब पहुंच रही है, इसलिए स्थायित्व और प्रगति पर जनसंख्या गतिशीलता के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।”



अतुल सहगल
(लेखक प्रबंध परामर्शदाता हैं)

भारत की बढ़ती मानव आबादी के बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। बढ़ती आबादी के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए एतदर्थ दायित्व बनने के खतरे पर बहुत चिन्ता जताई जा रही है। जनवरी 2024 में भारत की आबादी 1.44 बिलियन थी और वर्तमान में यह इससे थोड़ी अधिक हो सकती है। पिछले दशक के दौरान यह आबादी लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि जब तक जनसंख्या वृद्धि पर लगाम नहीं लगाई जाती, तब तक देश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता और विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। या, दूसरे शब्दों में, बड़ी आबादी राष्ट्रीय विकास और वृद्धि के लिए सबसे गंभीर अवरोधक

है। यह कितना सच है और क्या इस चिन्ता की पुष्टि करने के लिए कोई ऐतिहासिक मिसाल है? जनसंख्या के विषय का विश्लेषण बड़े, वैश्विक परिप्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए। दुनिया की आबादी आज 8 बिलियन के करीब है और पिछले 100 वर्षों में यह तीन गुना हो गई है। जनसंख्या को परिस्पष्टि या दायित्व मानने के बारे में मुख्य मुद्दा वैश्विक भौतिक संसाधनों के दोहन और उपयोग के वर्तमान प्रतिमानों और उन संसाधनों के स्वामित्व में भारी असमानता से संबंधित है।

मनुष्य अपनी इच्छा से बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, जैसे कि किसी कारखाने में सामान का उत्पादन किया जाता है। मनुष्य केवल निचले जानवरों की तरह सहवास और मैथुन कर सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कथित प्रगति के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में प्रजनन क्षमता में काफी तेजी से यह साबित होता है। वैज्ञानिक और चिकित्सा पेशेवर प्रजनन कोशिकाओं के निषेचन की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से गर्भधारण नहीं कर सकते। यह तर्कपूर्ण है

कि प्रकृति के कारखाने में एक अलौकिक, सर्वशक्तिमान इकाई को सूक्ष्म क्रिया द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। आप उसे निर्माता या भगवान कह सकते हैं जो दुनिया और बड़े ब्रह्मांड का नियंत्रक और नियामक भी है। यह एक प्रमुख वैज्ञानिक तथ्य है यदि विज्ञान को किसी भी विषय के व्यवस्थित और तार्किक उपचार के रूप में सही ढंग से समझा जाए। इसलिए जनसंख्या वृद्धि या गिरावट मनुष्य से अधिक ईश्वर का विषय है। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक है और मनुष्य को डर है कि यह मानव जीवन को अस्थिर बना देगा, तो उनके निर्माता को बेहतर पता है। वह जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग, चक्रवात, बवंडर, भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से मनुष्यों को उनकी गलतियों का एहसास कराता है। ये समय-समय पर अत्यधिक जनसंख्या को संतुलित करने का काम करते हैं। यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक विज्ञान ने जानलेवा बीमारियों पर विजय पाने और मनुष्यों की दीर्घायु बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है।

आज वैश्विक स्तर पर औसत जीवन प्रत्याशा 200 साल पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है। लेकिन यह वृद्धि पर्यावरण की कीमत पर हुई है। हमने फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों का भरपूर उपयोग किया है, जिसने मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को कम कर दिया है। हमने रासायनिक, रिडिक्शनिस्ट फॉर्मोलेशन-आधारित दवाओं और टीकों का भरपूर उपयोग किया है, जिनके गंभीर, छुपे हुए दुष्प्रभाव धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन हम स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए बिना इसे अनंत काल तक नहीं कर सकते। आज, मनुष्य पहले की तरह वैश्विक भौतिक संसाधनों को नष्ट और लूट रहे हैं। वे पर्यावरण की कीमत पर मानवीय सुख-सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता की कीमत पर जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। संक्रामक रोगों का मुकाबला मजबूत रासायनिक दवाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि घातक रूप से पुरानी बीमारियों और नई बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। मनुष्य

अनजाने में ही अस्थिर अस्तित्व की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। आइए हम अस्तित्व के प्रमुख आध्यात्मिक सत्यों पर वापस जाएं। ईश्वर सभी जीवन को नियंत्रित करता है। वह सभी ज्ञान का स्रोत है, जो वेदों नामक दिव्य रूप से प्रकट शास्त्रों में निहित है। ये शास्त्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित सभी ज्ञान का भंडार हैं। वैदिक भजन घोषित करते हैं कि प्रत्येक मानव जोड़े को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। वही वेद मनुष्यों को कम से कम 100 साल तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का आह्वान करते हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मानव आबादी एक संपत्ति है, न कि एक दायित्व। हमें यह जानना चाहिए कि जनशक्ति का उत्पादक और फलदायी उपयोग कैसे किया जाए। यदि हम वैदिक विज्ञान के अनुसार कृषि और खाद्य उत्पादन के तरीकों का पालन करते हैं, ऐसे विज्ञानों पर आधारित तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो हमें कभी भी मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरता से समझौता नहीं करना पड़ेगा और हम हर क्षेत्र में भरपूर फसल पैदा कर सकते हैं।

हम इसे पूरी तरह से जैविक खेती के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हुए, हम सिंथेटिक रासायनिक दवाओं का सहारा लिए बिना स्वस्थ स्वास्थ्य और लंबी आयु सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि आदमी जा रहा भारी भार असमानता को कम करने के लिए अपने जीवन जीने के तरीकों और प्रतिमानों को बदलना है, जहाँ वैश्विक आबादी के 20 प्रतिशत लोगों के पास वैश्विक संसाधनों का 80 प्रतिशत हिस्सा है। तालच के तुच्छ तत्व पर आधारित पूंजीवाद द्वारा संचालित हमारी आत्म-प्रशंसा की प्रवृत्ति ने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया है। जनसंख्या को एक संपत्ति माना जाना चाहिए और इसे एक संपत्ति माना जाना चाहिए और इसे एक संपत्ति माना जाए। यदि हम अपने जीवन के प्रतिमानों को प्रकृति के साथ संरेखित करने के लिए बदलते हैं और हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनते हैं।

चन्नी की बयानबाजी

खालिस्तान-समर्थक अमृतपाल सिंह का जेल में रहते हुए चुनाव जीतना भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी है। यह चुनाव आयोग और संविधान की किसी कमजोरी कड़ी की ओर भी संकेत करता है। अमृतपाल सिंह के समर्थन में बेशर्मा से संसद में कांग्रेसी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बयानबाजी अत्यन्त निन्दनीय है। यह परोक्ष रूप से राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए खालिस्तान व उपद्रवाद के समर्थन की तरह है। हालांकि, कांग्रेस ने स्वयं को अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से स्वयं को अलग किया, लेकिन क्या इतना काफी है? बात-बात में संसद में संविधान की प्रतियाँ लहराने वाले

कांग्रेसी इस मामले पर खामोश क्यों हैं? क्या खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चन्नी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? अतीत में भी कांग्रेस ने अकालियों का प्रभाव घटाने के लिए भिण्डराले जैसा भस्मासुर पैदा किया था जो बाद में इन्दिरा सरकार व भारत की अखण्डता के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। कर खड़ा हो गया था। आपरेशन ब्लूस्टार, इंदिरा गांधी की हत्या तथा सिख नरसंहार अभी जनता की स्मृतियों से समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संविधान के पीछे छिप कर कांग्रेस देश में अलग-अलग किस्म के भस्मासुर पैदा करना चाहती है?

- नरेन्द्र टोंक, मेरठ

आप की बात

कोचिंग सेंटरों पर लगाम

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें स्टडी सेंटर की बिल्डिंग के मालिक के चार भाई भी शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक एवं उसके साथी को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हलवा देश के 99 प्रतिशत प्रतिशत लोगों को नहीं मिलता केवल 3 प्रतिशत ही इसे पाते हैं। राहुल गांधी बार-बार देश की सर्वोच्च सत्ता से दलितों व ओबीसी के बाहर रहने का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह प्रवृत्ति तो उनके पूर्वज व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुई थी और कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में इसे बढ़ावा दिया। अनेक दस्तावेजों से स्पष्ट है कि नेहरू जातिगत आरक्षण के

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

राहुल की समझ

राहुल गांधी ने बजट पर बहस में बजट तैयार करने के पहले परंपरागत हलवा आयोजन का मजाक उड़ाते हुए चित्र दिखाया। उन्होंने कहा कि हलवा देश के 99 प्रतिशत प्रतिशत लोगों को नहीं मिलता केवल 3 प्रतिशत ही इसे पाते हैं। राहुल गांधी बार-बार देश की सर्वोच्च सत्ता से दलितों व ओबीसी के बाहर रहने का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह प्रवृत्ति तो उनके पूर्वज व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुई थी और कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में इसे बढ़ावा दिया। अनेक दस्तावेजों से स्पष्ट है कि नेहरू जातिगत आरक्षण के

खिलाफ थे तथा महात्मा गांधी की दलितोद्धार संबंधी बैठकों में भाग लेने वाले अनेक कांग्रेसी लौट कर स्वयं को पवित्र करने के लिए अपने ऊपर गंगा जल छिड़कते थे। क्या राहुल गांधी यह बता सकते हैं कि कांग्रेस सरकारों ने कितने दलितों व ओबीसी को मौका दिया और क्या मोदी सरकार इस मामले में उनसे बेहतर नहीं है? संसद में अंबेडकर का चित्र तक न लगाने देने वाली कांग्रेस आज राहुल के नेतृत्व में जो ढोंग कर रही है, उसे देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन राहुल की समझ अभी-बालक बुद्धि से आगे नहीं पहुंची है। शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

ओलम्पिक का महत्व

चार साल में एक बार होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ी वर्षों तक परिश्रमपूर्वक तैयारी करते हैं। दुनिया के राग-रंग और मनोरंजन को त्याग कर सीधे लक्ष्य पर निगाहें रहती हैं। मनु भाकर को निशानेबाजी में मिले कांस्य पदक के पीछे भी ऐसा ही परिश्रम छिपा है। उम्मीद है कि इस ओलंपिक में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। मेडल का फैसला तो कुछ घंटों में आ जाता है। मगर उनके पीछे छुपा श्रम सबको नजर नहीं आता है। हमारा देश आजादी के बाद से सिर्फ हॉकी में ही पदक प्राप्त करता रहा है। पिछले कुछ

ओलंपिक से ही उसने अन्य खेलों पर ध्यान दिया है। इससे कभी मात्र एक कांस्य पदक लाने वाला देश आज दो अंकों में पदक लाने की क्षमता रखता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। विडंबना है कि ओलंपिक मैचों के दरमियान भी कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो तो बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक क्रिकेट ही देखते नजर आएं। शायद चीन के सर्वाधिक स्वर्ण पदक करने का राज भी यही है कि वहां क्रिकेट होता ही नहीं। ओलंपिक का महत्व समझते हुए हमें सभी खेलों पर ध्यान देना होगा। -विभूति चुपक्या, खाखरोद

चलेगा स्वच्छता अभियान, सभी को करना है श्रमदान: जिलाधिकारी

संवाददाता। संतकबीरनगर

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में गौरवशाली इतिहास, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय एकता की याद दिलाने वाला 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त 2024 को जनपद में परम्परागत रूप से हर्षोल्लास एवं आकर्षक ढंग से मनायें जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सत्यजित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश व मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यह परम्परा रही है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसके लिए विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रमों के सुचारु एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की



जिम्मेदारी सुनिश्चित की गयी है। इस हेतु सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन दो महत्वपूर्ण कार्यों जिसमें श्रमदान के आधार पर वृहद स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान को शामिल किया जाएगा, जिसमें हम सब मिलकर स्वयं अपने जनपद में जन सहभागिता के साथ श्रमदान कर जनपद के प्रत्येक गांवों एवं शहर के सभी वाडों में साफ-सफाई का कार्य करेंगे, जिसकी सूचना

से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दिया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ निरपेक्षता, समाजिक समरसता, तथा सम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा, ध्वजारोहण के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा देश पर शहीद हुए देश भक्तों के जीवन की प्रेरक प्रसंग दोहराये जाएंगे। इसमें श्रमदान के आधार पर आम जनमानस, स्वयं सेवी संस्थाओं, रोटी क्लब सहित अन्य स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने की चकबंदी कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक



अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने टाइमलाइन के अनुसार कार्य करने के साथ ही पुराने गांव जो चकबंदी में चल रहे हैं उनको शीघ्र कब्जा परिवर्तन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चकबंदी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि टाइमलाइन के अनुसार काम किया जाना है जो अधिकारी टाइमलाइन से कार्य नहीं करेंगे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। डीएम ने

सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, उप संचालक चकबंदी अधिकारी को टाइमलाइन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गांव का कब्जा परिवर्तन कराए जाएं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि पुराने गांव चकबंदी में चल रहे हैं उनको शीघ्र कब्जा परिवर्तन किया जाये ताकि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़े। चकबंदी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 52 ग्रामों में चकबंदी की जानी है जिसके सापेक्ष 03 ग्रामों की धारा 52 कर चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 5 ग्रामों का कब्जा परिवर्तन कर दिया गया है। टाइमलाइन बनाकर कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इन गांवों को कब्जा परिवर्तन करा दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्र, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी केलेकर सिंह, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी आदि मौजूद रहे।

15 राज्यानुदानित मदरसों की जांच के लिए डीएम ने गठित की जांच समिति

संवाददाता। संतकबीरनगर

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उप, लखनऊ के पत्र एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर के जांच आख्या के आधार पर तत्परता से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के क्रम में जनपद में संचालित 15 राज्यानुदानित मदरसों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षक शिक्षणकर कर्मचारियों की उपस्थिति एवं मिड-डे-मील की जांच किए जाने हेतु जांच समिति का गठन कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खण्डवार मदरसों की जांच हेतु गठित जांच समिति में मदरसा अरविश्या अयुगुल बहल्ल उलूम अनसरा टोला खलीलाबाद एवं मदरसा जामिया अरबिया अयुगुल मिस्नाहूत

उलूम विधियानी, खलीलाबाद में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षक शिक्षणकर कर्मचारियों की उपस्थिति एवं मिड-डे-मील की जांच किए जाने हेतु जांच समिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी खलीलाबाद को नामित किया गया है। इसी प्रकार मदरसा दारुत उतुम अहले सुन्नत गौसिया रिजविया अगया, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत रिजविया दशावा, मदरसा दा0 उ0-अ0सु0 तदरीसुल इस्लाम बसडीला, मदरसा जामिया कलौमिया अहलेसुन्नत अजीजुल उलूम लोहरसन, मदरसा दा0 उ0 अहमदिया मेराजुल उलूम, धर्मसिंहवा एवं मदरसा दा0 उ0 अ0सु0 अनवारुल इस्लाम महदेवा नानकार, बौरव्यास की जांच हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी

सेमरियावा/सांथा एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सेमरियावा, सांथा को नामित किया है। इसी प्रकार मदरसा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी मिस्नाहल उलूम झिंगुरापार रौजा महलौली एवं मदरसा रिजविया अहलेसुन्नत रस्तमपुर, शनिचरा बाजार की जांच हेतु नामित जिला कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी नाथनगर/पौली एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नाथनगर पौली को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार मदरसा दा0उ0 अ0सु0 तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा, बखिरा, मदरसा दा0 उ0 मोहम्मदिया लेडुआ-महुआ, बखिरा एवं मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम नौरों, बखिरा की जांच हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी बघौली एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बघौली को नामित किया गया है।

अल्ट्रासाउंड सेंटरों की अचानक जांच में मिलीं खामियां



संतकबीरनगर। सीएमओ के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान तीन सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिले। जिसके चलते इन सेंटरों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही संचालक को कागजात लेकर तलब किया गया है। टीम के छापेमारी की सूचना पर अन्य अल्ट्रासाउंड संचालक फरार हो गए। टीम में शामिल अपर सीएमओ डॉ शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ मुन्नाकर अली के साथ स्वास्थ्य टीम ने शहर के सिटी अल्ट्रासाउंड, सुपर डायग्नोस्टिक सेंटर

बड़गो, केयर अल्ट्रासाउंड सीएचसी खलीलाबाद के सामने, अब्बासी डायग्नोस्टिक सेंटर बैंक चौराहा, विश्वास अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया। जिसमें सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर, सुपर डायग्नोस्टिक सेंटर और केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर बैंक चौराहा पर पंजीकृत चिकित्सकों के जरिए अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा था। कुछ अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। जिसके कारण इन सेंटरों को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही संचालक को सेंटर के कागजात के साथ तलब किया गया है।

आमी नदी में डूबने से हुई दो किशोरियों की मौत

संतकबीरनगर। बेलहर थाना क्षेत्र के पड़रिया स्थित आमी नदी में नहाने के दौरान पानी में डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गयी। किशोरियों की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। दोनों किशोरियां बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गजोत की रहने वाली थीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। जानकारी के अनुसार दुर्गजोत निवासिनी सहेना पुत्री मन्ना 9 वर्ष व इशरत जहां उर्फ सोनी पुत्री मुनाफ 10 वर्ष मलंग शाह बाबा के मजार के पीछे आमी नदी में एक साथ नहाने गयीं थीं। इसी दौरान पैर फिसलने से वे नदी के गहरे पानी में चली गयीं। आस-पास के लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक दोनों लड़कियां सहेना इशरत जहां गहरे पानी में डूब गयीं। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों व पुलिस की मदद से नदी में कूदकर दोनों को ढूँढा गया। घटनास्थल से दोनों को निकला गया दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया।

डीएम ने की विकास कार्यों में कम ग्रेड प्राप्त योजनाओं की समीक्षा



श्रावस्ती, भिनगा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों में कम ग्रेड प्राप्त योजनाओं की समन्वित विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के साथ कार्य करके सीएम डैशबोर्ड पर अपने विभाग की रैंकिंग में आप्रोक्षित सुधार लाएं और विकास कार्यक्रमों में तेजी लाकर जनपद की रैंकिंग बढ़ाने की मांग की। विकास कार्यों की प्रगति में विभागीय अधिकारी की प्रगति में

शिथिलता पायी गई तो निश्चित ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि माह जून 2024 में जनपद श्रावस्ती को विकास कार्यों एवं राजस्व के सम्बन्ध में 43 वीं रैंक है जिसमें कुल 77 कार्यक्रमों में से 29 कार्यक्रमों में बी, सी, डी व ई ग्रेड प्राप्त हुये हैं। बी सी डी व ई ग्रेड से सम्बन्धित विभागों में उर्जा कृषि ग्राम्य विकास ग्रामीण अभियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दुग्ध जलापान नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति पंचायतीराज पर्यटन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्राथमिक शिक्षा पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्याण महिला एवं बाल विकास लोक निर्माण विभाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं सिंचाई एवं जल संसाधन के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विकास कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये।

डीएम ने किया सीएचसी व शहरी निकायों का निरीक्षण



रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रतापुर स्थित एकता विहार कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिया कि शादी विवाह, जन्मोत्सव आदि अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान यहां पर साफ सफाई, जलजी, पानी और सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जाए। वंदन योजना के अंतर्गत अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली के नाम से चल रहे सौन्दरीकरण कार्य के दौरान मुशौंगंज स्थित शहीद स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटन विभाग और संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि कार्य के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। डीएम ने किला बाजार स्थित बड़ा कुआं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सौन्दरीकरण कार्य के अंतर्गत इसका भी कायाकल्प किया जाए।

इनर व्हील वलब ने छात्राओं को कैसर के प्रति जागरूक किया



रायबरेली। इनर व्हील क्लब द्वारा स्थानीय खाली सहाट में स्थित लाल कन्या ऋषि इंटर कॉलेज में कैसर के प्रति जागरूकता लाने पर शंकुस कैसर अस्पताल की डॉक्टर समीक्षा मिश्रा द्वारा छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर एवं विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पूनम वर्मा को पौधा देकर किया गया। अध्यक्ष दीपि सिक्करिया ने सभी छात्राओं, अध्यापिकाओं व क्लब की सदस्याओं का स्वागत व अभिनंदन किया। डॉक्टर ने प्रोजेक्टर पर छात्राओं को कैसर का कारण तंबाकू, मदिरा सेवन, पान व पान मसाला

आदि को बताया और बच्चों से अपील की कि इनका सेवन न करें न किसी को करने दें। खास करके महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैसर वी गर्भाशय कैसर के प्रति छात्राओं को जानकारी दी बच्चों ने प्रण किया कि हम अपने परिवार, व पड़ोस और जानने वालों को पान मसाला धूम्रपान व मदिरा इनका सेवन न करें सभी को इसके लिए जागरूक करें। पीडीसी ज्ञान लता गुप्ता ने भी बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताईं। कार्यक्रम अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिन बंदियों के पास निजी वकील न हों उन्हें विधिक सहायता दिलाएं

●जिला न्यायाधीश ने कारागार का निरीक्षण कर दिये निर्देश

संवाददाता। उर्ई, जालौन



उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अध्यक्ष, जनपद न्यायाधीश अचल सच्चंद ने आज जिला कारागार उर्ई का मासिक भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरुद्ध बंदियों से पूछताछ करते हुये उनकी समस्याओं को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर सचिव, अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव सरन एवं जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। निरीक्षण में जिला जज ने बंदियों के मुकदमों को पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता,

सलाह और महिला बंदी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान इत्यादि के बारे में जाना-परखा। उन्होंने कई बंदियों से सुविधा-अलग जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बंदी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बंदी को पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो

संबंधित न्यायालय में बंदी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार जो बंदी दोषसिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी दी। प्रमुख सचिव रवींद्र ने पशु प्रजनन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और अर्जेंट इंडिया के सचिव, डॉ. सी पी देवानंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आंडियो और वीडियो के माध्यम से एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य उच्च वंशावली के सांडों और अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर देश में गाय-भैंस की दुग्ध नस्लों का दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी दी। प्रमुख सचिव रवींद्र ने पशु प्रजनन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सभा अध्यक्ष नारायण को होना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता कब पड़े, किसी को नहीं पता और

प्रमुख सचिव ने किया पशु प्रजनन केंद्र का भ्रमण

सलोन, रायबरेली। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव -पशुधन, मत्स्य व दुग्ध विकास विभाग रवींद्र ने पशु प्रजनन अनुसंधान केंद्र सलोन का भ्रमण किया और वहाँ की गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक और अर्जेंट इंडिया के सचिव, डॉ. सी पी देवानंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आंडियो और वीडियो के माध्यम से एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य उच्च वंशावली के सांडों और अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर देश में गाय-भैंस की दुग्ध नस्लों का दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी दी। प्रमुख सचिव रवींद्र ने पशु प्रजनन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सभा अध्यक्ष नारायण को होना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता कब पड़े, किसी को नहीं पता और

मैडिकल कालेज में बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं सीपीआर डे मनाया गया



उर्ई, जालौन। मंगलवार को बाल रोग विभाग, राजकीय मैडिकल कॉलेज जालौन एवं भारतीय बाल रूप अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में, प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद त्रिवेदी के अध्यक्षता में, राजकीय मैडिकल कॉलेज जालौन के लेक्चर थिएटर में, बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं सीपीआर डे मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर त्रिवेदी ने बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) की जानकारी न केवल मैडिकल प्रोफेशनल बल्कि देश के सभी जागरूक नागरिकों को होना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता कब पड़े, किसी को नहीं पता और

अगर हम समय से ज़रूरतमंद को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे दें, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। भारतीय बाल रोग अकादमी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता प्रोफेसर जीएस चौधरी ने बताया की हमारे देश में 2 प्रतिशत से कम लोगों को सीपीआर के बारे में पता है, जबकि हमारे देश में 112 लोगों की हर मिनट सीपीआर देने आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर इसको करने के लिए बहुत ही कम लोग मिल पाते हैं। इसलिए हमें एक बृहद अवेयरनेस प्रोग्राम का तरोह इसके चलकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भारतीय बाल रोग अकादमी जो कि बच्चों की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है, इस तरह का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठया है। इसी क्रम में डॉ छवि जायसवाल सचिव भारतीय बाल रोग अकादमी जालौन ने सीपीआर के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

तैनाती स्थल से सीडीपीओ रहते नदारद कैसे संभालेंगे दो कार्यालयों का प्रभार

उर्ई, जालौन। जनपद के महैवा ब्लॉक में बाल विकास एवं पुष्पहर कार्यालय का चार्ज सीडीपीओ के पद पर शरद अवस्थी ने 2022 में संभाला था। जो अपने तैनाती कार्यालय में अपनी मर्जी से जाते थे। अब उन्हें रामपुरा ब्लॉक में तैनात कर दिया गया है और महैवा ब्लॉक का भी अतिरिक्त चार्ज मिला है। बता दें कि महैवा बाल विकास विभाग परियोजना में शरद अवस्थी दो वर्ष से तैनात हैं और अब उन्हें रामपुरा तैनात कर दिया गया है। लेकिन ब्लॉक के मुख्य द्वार के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा जाये तो इनकी उपस्थित महीनों के हिसाब से मिलेगी। इनकी अधिकांश नौकरी कानपुर से ही बिना विभागीय कम किये अभी तक चलती आ रही है। जिसपर न कभी डीपीओ इफ्तखार अहमद ने एतर्जज जाताय और न ही महैवा ब्लॉक में तैनात बीडीओ संदीप मिश्रा ने जिले के उच्चधिकारियों को अवगत कराने की जहमत उठाई जिसके चलते शरद अवस्थी की नौकरी दो वर्ष से कानपुर रहकर की जा रही थी। वह सिर्फ बड़ी मीटिंगें ही अटेंड करते रहे। सूचों की मर्त तो एक महिला कर्मचारी को दबा धमकाकर कार्यालय चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। अब इनके पास दो ब्लॉक की बाल विकास विभाग के परियोजनाओं की जिम्मेदारी है। बात यह है कि अभी तक एक ब्लॉक की परियोजना बर्बाद थी। अब इन्हें दो परियोजनाओं का चार्ज मिल गया है। तो अब दोनों ब्लॉक में बाल विकास विभाग का क्या हाल होगा इस बात का अंदाजा इनकी महैवा की तैनाती से लगाया जा सकता। यह बात जरूर है की अगर डीपीओ की कृपा बरसती रही तो जरूर दोनों ब्लॉक ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे अभी तक महैवा ब्लॉक कानपुर बैठकर चला रहे हैं। जब इस संबंध में विभागीय अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तखार अहमद से बात की गई तो उनका कहना है कि विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के चलते यह सब चल रहा है। साथ यह भी बताया की वह औरैया जिले के डीपीओ के पद पर रह चुके हैं इसलिए उनका सीडीपीओ की कुर्सी पर मन नहीं लगता।

खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध लामबंद हुए ग्रामीण

- भाजपा नेता ने फिर की डीएम से शिकायत
- छुटा धूम रहे अन्ना गोवर्षों से किसान परेशान
- विवादित बीडीओ पर कार्रवाई न होने से क्षेत्रीय लोगों में रोष



में बताया कि ग्राम पंचायत चंद्ररसी और उसके मजरा नागवां में दो वर्षों से अन्ना गोवर्ष किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। बीडीओ प्रतिभा शाल्या शिकायत करने वाले किसानों से अप्रद भाषा बोल कर कार्यालय से भगा देती है, अन्ना गोवर्षों से किसानों को निजात नहीं मिल रही है। अन्ना गोवर्षों से परेशान किसानों का कहना है कि गांव और उसके आसपास अन्ना गोवर्ष बड़ी संख्या में हैं। जो आए दिन किसानों की तिल और मूंगफली की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, दो सप्ताह पूर्व लिखित शिकायत के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर बीडीओ कदौरा प्रतिभा शाल्या गांव पहुंची और किसानों को आश्वासन

दिया कि गोवर्ष समीप की गोशाला में बंद करा दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने दो दिन बाद खानापूर्ति करते हुए गांव के पशुपालकों के कुछ गोवर्ष बरसेही गोशाला में शिफ्ट कराकर फेंटे और वीडियो बना लिया और बरसेही कदौरा का खुला समर्थन कर रहे हैं। इसलिए बीडीओ कदौरा अपनी मनमानी पर उतारू हैं। भाजपा नेता और किसान ने 23 जुलाई को मनरेगा में बिना कार्य के फर्नी भुगतान करने, खाली गोशालाओं में गोवर्षों की फर्नी डिमांड लगाकर बंदरबांट करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। जिसकी जांच डीएम ने सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को दी थी। लेकिन अभी तक सीडीओ ने जांच शुरू नहीं की।

बोली की मैं किसी से डरती नहीं हूं। तुम लोगो ने ज्यादा शिकायत की तो पुलिस बुला कर थाने की हवा खिलावा दूंगी। डर बस हम लोग वहां से लौट आए। 23 जुलाई को आपके कार्यालय में आकर एडीएम नामानि गंगे विशाल यादव को शिकायती पत्र दिया था। एडीएम ने कहा था कि अभी जाओ, एक दो दिन बाद सीडीओ से बात कर लेना, जब हम लोगों ने सीडीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा की इस मामले की बात तुम लोगो बोडीओ से कहो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। सीडीओ, बीडीओ कदौरा का खुला समर्थन कर रहे हैं। इसलिए बीडीओ कदौरा अपनी मनमानी पर उतारू हैं। भाजपा नेता और किसान ने 23 जुलाई को मनरेगा में बिना कार्य के फर्नी भुगतान करने, खाली गोशालाओं में गोवर्षों की फर्नी डिमांड लगाकर बंदरबांट करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। जिसकी जांच डीएम ने सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को दी थी। लेकिन अभी तक सीडीओ ने जांच शुरू नहीं की।

भदेख में दबंगों ने आम रास्ते में किया अवैध कब्जा

कुर्दौद, जालौन। विकासखंड अंतर्गत ग्राम भदेख में सैयद बाबा के बगल से बहुत पुराना रास्ता नक्शा नजरी में अंकित है और वहां से सभी का आना-जाना रहता है जहां यादव समाज के लोगों के द्वारा जबरन खूंट्टा गाड़ कर पशुओं को बांधना भारी मात्रा में कीचड़ पैदा कल रास्ते में पशुओं को बांधना जिससे विश्वकर्मा समाज के मोहल्ले निवासियों को आने-जाने में काफी तकलीफ पैदा हो रही है जबकि राज किशोर विश्वकर्मा के द्वारा कई बार लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन देते हुए लेखपाल के द्वारा नापतोली करवा कर सही जानकारी हासिल करने आए दिलाने की बात कही है इसके बावजूद भी दबंगों ने रास्ता में कीचड़ इतना फैला रखा है सुबह शाम निकालने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है जिससे शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई मौका मुआयना कर लेखपाल के जरिए इस रास्ते पर अवैध कब्जा हटवाया जाना सुनिश्चित कर विश्वकर्मा समाज के लोगों को न्याय दिलाया जाए।

सीसी सड़क बनवाने का झांसा दे खड़जे की ईटें उखाड़ गौशाला में बिछाई

संवाददाता। जालौन, उर्ई



लगभग एक वर्ष पूर्व गांव में प्रधान प्रतिनिधि व सचिव ने खड़जा की ईटें उखाड़कर सीसी रोड डलवाने का आश्वासन दिया। उखाड़ी गई ईटों को अन्य स्थान पर प्रयोग कर अब तक सीसी सड़क नहीं डलवाई गई है। जिसके चलते ग्रामीण दलदल से होकर निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रधान व सचिव ने मिलीभगत कर गौशाला व अन्य स्थान पर पुराने ईटा बिछाने को पुण्युप तरीके से भुगतान भी निकालकर हड़प कर लिया। पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जांच कराने एवं गांव में सीसी रोड डलवाने की मांग की है। ब्लॉक के ग्राम सहाय निवासी लालबहादुर, रमोले, राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र, प्रमोद कुमार, महेंद्र कुमार आदि ने जिलाधिकारी राजेश पांडेय को शिकायती पत्र भेजकर

लिखा कि उनके गांव में वाई नंबर दो में आम रास्ते पर ईटों का खड़जा डाला गया था। जिससे होकर ग्रामीण आवागमन करते थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगभग एक वर्ष पूर्व उनके वाई में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व सचिव आए और खड़जा की ईटों को उखाड़ने लगे। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस स्थान पर सीसी रोड डाला जाना है। इसलिए ईटों को उखाड़ा जा रहा है। इसके बाद उखाड़ी गई ईटों को गौशाला एवं अन्य स्थान पर लगा दिया गया। बाद में पता चला कि ग्राम

प्रधान व पंचायत सचिव ने गौशाला व अन्य स्थान पर पुराने ईटा का खड़जा बिछाकर उसका चोरी छिपे भुगतान भी निकाल लिया। जबकि एक वर्ष से खड़जा के स्थान पर सीसी रोड की शुरूआत तक नहीं हो सकी है। बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़ होकर दलदल हो गया है। कीचड़ के चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व वाई में सीसी रोड बनवाने की मांग की है।

सीडीओ की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के जिला टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न दिए निर्देश

● अक्टूबर तक निपुण बनाएं परियोजना द्वारा निर्धारित विद्यालय

● बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय जनपद में संचालित ना हो अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार कार्यवाही के लिए रहे तैयार सीडीओ



निपुण विद्यालय के रूप में घोषित हो। इसके लिए इन विद्यालयों की खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी एवं एआरपी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। ऑपरेशन कायकल्प के अंतर्गत जो भी भवन नवनिर्मित हैं उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग को शीघ्र स्थानांतरित कर दिया जाए। जिन विद्यालयों में गंदगी झाड़ियां नाली चौक जैसी समस्या हो वह प्रत्येक सप्ताह अवगत कराएं। बीएसए सुनिश्चित करें कि बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय जनपद में संचालित ना हो

अन्यथा की स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भी सही मानक जांच लिए जाएं। बीआरसी में स्थापित आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास का सदुपयोग करते हुए अपेक्षित जिला समन्वयक सौरभ बनारस बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान में दक्ष बनाया जाए। बीआरसी या विद्यालय में किसी भी प्रकार की निशुल्क पुस्तकों या निशुल्क दवाइयों का संग्रहण ना दिखाई दे अन्यथा पूरे

विद्यालय स्टाफ पर कार्यवाही की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी मनोज सिंह पटेल चंद्रजीत सिंह अजय सिंह संजय कुमार गुप्ता श्रीकृष्ण प्रेमी सपना सिंह अजीत प्रताप सिंह जिला समन्वयक सौरभ श्रीवास्तव अरुणेश सचान देशवीर सिंह अजय कुमार अश्वनी आनंद अमित दीक्षित विनय विश्वकर्मा राजीव कुमार एसआरजी अनंत त्रिवेदी संत कुमार दीक्षित आदि उपस्थित रहे।

केजरीवाल की गिरफ्तारी को खारिज करने का राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

संवाददाता। फर्रुखाबाद

इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी (घटक) ने आज राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को खारिज करके इलाज करने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए तथा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी बंद करने की मांग की गई। सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी (घटक) जिला अध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य के नेतृत्व में 'इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी' के करीब दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय प्लेगहट पहुंचकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी एवं जेल में प्रताड़ित किए जाने के मामले से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन आज एक मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

इस दौरान इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के नाम पर राज नैतिक षड्यंत्र के तहत अवैध ढंग से जेल भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि आज तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत ई डी, सीबीआई, कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गई। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान होकर पार्टी को ही खत्म करना चाहती है। उन्होंने केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को से तुरंत खारिज करके उन्हें सम्माना रिहा किए जाने की मांग की। इस अवसर पर सपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव, कांग्रेस के कौशलेन्द्र सिंह यादव, जनता दल (एन) के लालराम वर्मा जिला सचिव साहब सिंह साहब शाक्य आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

सूखे के अदेशे से अन्नदाताओं का कांप रहा कलेजा

● बारिश न होने से सूख रही धान की फसल

● जरीली पम्प केनाल से भी किसानों का नहीं हो पा रहा मला

मिल पाने से धान का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। मानसून की बेरुखी के चलते बहुत से किसान तो रोपाई तक नहीं कर पाए हैं। असेाथर क्षेत्र में स्थापित जरीली पम्प केनाल से भी किसानों का भला नहीं हो पा रहा है। धान लगे खेतों की सिंचाई किसान नलकूप, नहर और अन्य संसाधनों से कर रहे हैं लेकिन अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण हर सप्ताह में खेत पानी मांग रहे हैं। ऐसे में सिंचाई के आभाव में खेतों में जगह जगह दरारें आ रही हैं।

पानी के आभाव में पैदावार होगी प्रभावित: किसानों की मानें तो यदि इस समय पानी न मिलता तो पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। महंगे डीजल और बिजली की सिंचाई करने में किसानों को बहुत अधिक राशि लगानी पड़ रही है। बिजली भी समय से नहीं मिल पा रही है तथा कटाई के साथ क्षेत्र में आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं की जा रही है। इसकी वजह से फसल की सिंचाई करना किसानों के लिए

नामुमकिन सा है। सस्ता डीजल और नहरों में पानी छोड़ने की मांग: किसान रविदेव सिंह, दिनेश सिंह, धर्मप्रकाश मोय, जयसिंह मोय, दुर्गेश मोय आदि ने बताया कि इस समय धान की फसल में कल्ले बनने की अवस्था में है। ऐसी परिस्थिति में खेत में नमी बनाए रखना अति आवश्यक है। डीजल महंगा होने के कारण सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने सरकार से सस्ता डीजल, प्यास मात्रा में बिजली के साथ साथ सभी नहरों में डेड से लेकर टेल तक पानी पहुंचाए जाने की मांग की है।

सारे संसाधन दे रहे दगा: इस समय नहर में पानी भी नहीं आ रहा है। जरीली पंप केनाल आए दिन बंद कर दिया जाता है। सुजाणपुर जबहरे की डेड प्रत्येक दिन चार पांच बार कर्मचारियों द्वारा बंद कर देने से कुलाबे में पानी नहीं पहुंच पाता। इसके कारण किसानों की अधिकतर फसल सूखने की कगार पर है। यदि दो चार दिन और बारिश न हुई तो धान की फसल पूरी तरह सूख जाएगी।

जिला कारागार का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण

गुरसहायगंज (कन्नौज)। जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला व अपर पुलिस अधीक्षक डा. संसार सिंह द्वारा सम्पूर्ण कारागार का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार के सभी अहातों की बैरकों में निरूद्ध बंदियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी, बैरकों की तलाशी करायी गयी, तलाशी के दौरान कोई निषिद्ध वस्तु नहीं पायी गयी।



जिला कारागार में निरीक्षण करते डीएम व एसपी।

जनपदीय अधिकारियों द्वारा बंदियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी परन्तु किसी भी बंदी द्वारा कारागार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बतायी गयी। कारागार में पर्याप्त सफाई पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े उपकरणों की क्रियाशीलता को देखा गया। अक्रियाशील कैमरों को तत्काल ठीक कराये जाने तथा कैमरों को प्रत्येक समय क्रियाशील रखे जाने व उनकी प्रत्येक समय मनीटरिंग करने के निर्देश दिये गये। अस्पताल

को सुगमतापूर्वक संचालन हेतु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह बीमार बंदियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। कारागार में निरूद्ध वृद्ध व अशक्त बंदियों पर विशेष निगरानी रखे तथा उनका नियमित रूप से परीक्षण कर समुचित उपचार करना सुनिश्चित करे। निरीक्षण के दौरान जनपदीय अधिकारियों द्वारा कारागार

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की नगरवासियों को दी जानकारी

संडीला (हरदोई)। नगर पालिका परिषद एवं दो अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से नगर में किए जा रहे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की जानकारी नगरवासियों को दी गयी। जूनियर हाई स्कूल में आयोजित इस मेगा इवेंट में नगर के आईआर इंटर कॉलेजए मीरा बाई सरस्वती इंटर कॉलेजए गाथित्री इंटर कॉलेजए पार्वती एवं रामप्यारी स्मारक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक़ड नाटक तथा अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर चैयमैन मो० रईस अंसारी ने बताया कि नगर में सफ़ाई और कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण की योजना चला रही है। इसमें सूखा तथा गीला कचरा अलग अलग निर्धारित पॉइंट्स में ही डालने के साथ साथ कूड़ा सड़का अथवा खाली पड़े हुए प्लांटों पर न डाला जाए क्योंकि कचरे के उचित प्रबंधन से ही नगर को स्वच्छ और निर्बल बनाया जा सकता है।

बाढ़ प्रभावित धरू क्षेत्र कीरतनगर पहुंची डीएम व एसपी लगाई चौपाल

● डीएम.एसपी ने अफसरों संग बाटी प्रभावित परिवारों को स्पेशल किट, खिले चेहरे

लखीमपुर खीरी। मंगलवार को अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा और सीडीओ अभिषेक कुमार संग तहसील पलिया की सुदूरवर्ती बाढ़ से प्रभावित थारू क्षेत्र कीरतनगर पहुंचीए जहा उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में ग्राम चौपाल लगाई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में थारू जनजाति की युवतियों ने उनका पुष्पवर्षा कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। ग्राम चौपाल का शुभारंभ डीएम,एसपी, सीडीओ ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर की। विद्यालय की छात्रा सोनावती, खुशश्रू, अनुकला, जयशकुमारी ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। संगम गुप की थारू जनजाति की महिलाएं ने भी अपनी मनमोहक और शानदार



प्रस्तुति दी। चौपाल का संयोजन एवं संचालन एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह ने किया। ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि उन्हें थारू समाज से मिलकर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। आपके बीच आकर संवाद करना हमारा सौभाग्य है। थारू क्षेत्र की बालिकाओं व महिलाओं में भी अपार कौशल व कुशलता है। सरकार की ओर से जनजातियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा

रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किए जाने वाली कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। कहा कि आज प्रदान की जाने वाली किट का सदुपयोग करें। इसमें शामिल पांचो वस्तुएं आपके लिए कामे उपयोगी है। एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार ने भी इस सुदूरवर्ती गांव में आने और सभी से मिलकर खुशी जाहिर की। सीडीओ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी किट के अलावा डीएम ने अभिभव पहल के तहत स्पेशल किट तैयार कराई है।

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की नगरवासियों को दी जानकारी

संवाददाता। संडीला (हरदोई)

नगर पालिका परिषद एवं दो अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से नगर में किए जा रहे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की जानकारी नगरवासियों को दी गयी। जूनियर हाई स्कूल में आयोजित इस मेगा इवेंट में नगर के आईआर इंटर कॉलेज, मीरा बाई सरस्वती इंटर कॉलेज, गाथित्री इंटर कॉलेज, पार्वती एवं रामप्यारी स्मारक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक़ड नाटक तथा अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।



पुरस्कृत करते चेयमैन

चैयमैन मोहम्मद रईस अंसारी ने बताया कि नगर में सफ़ाई और कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण की योजना चला रही है। इसमें सूखा तथा गीला कचरा अलग अलग निर्धारित पॉइंट्स में ही डालने के साथ साथ कूड़ा

सड़क अथवा खाली पड़े हुए प्लांटों पर न डाला जाए क्योंकि कचरे के उचित प्रबंधन से ही नगर को स्वच्छ और निर्बल बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी विजेता गुप्ता, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राज गंमल सिंह, नपा के कई सभासद एवं सीडीसी और एचसीएल के पदाधिकारी मौजूद छत्रे। प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया।

स्वाज्जदोष बीमारी नहीं, यह एक प्राकृतिक एवं सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है: डा. गिरिराज

पुखरायगं, कानपुर देहात। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौधा में स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को किशोरावस्था में होने बदलावों एवं समाज में फैले मिथकों की जानकारी दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौधा के चिकित्सक डा० गिरिराज ने बताया कि स्वप्नदोष कोई बीमारी नहीं है। यह एक प्राकृतिक और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें सोते समय शुक्राणु का स्राव होता है। किशोरावस्था में ऐसा होना आम बात है। वहीं एमआरपी दिनेश यादव ने बताया कि महिलाओं में मासिक धर्म भी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत के कई हिस्सों में, मासिक धर्म को अभी भी गंदा और अशुद्ध माना जाता है। खासकर हिंदू धर्म में, मासिक धर्म



शिक्षकों को जानकारी देते एमआरपी दिनेश

के दौरान महिलाओं को सामान्य जीवन में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। जबकि उसे अपने परिवार और जीवन के दिन-प्रतिदिन के कामों में लौटने से पहले शुद्ध होना चाहिए। इसलिए, इस धारणा के बने रहने का कोई कारण नहीं लगता कि मासिक धर्म वाली महिलाएं अशुद्ध होती हैं। कई लड़कियों और महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वे

मासिक धर्म से गुजर रही हैं। जिसमें शहरी लड़कियों के बीच पूजा कक्ष में प्रवेश न करना प्रमुख प्रतिबंध है। जबकि ग्रामीण लड़कियों के बीच रसाई में प्रवेश नहीं करना मुख्य प्रतिबंध है। मासिक धर्म वाली लड़कियों और महिलाओं को प्रार्थना करने और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी प्रतिबंधित किया जाता है। इस मिथक का अंतर्निहित आधार मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता की सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं।

डीएम-एसपी ने 207 प्रशिक्षणार्थियों को बाटे निःशुल्क टूल किट, प्रमाण पत्र, खिले चेहरे

● डीएम बोली, जनजातीय क्षेत्र की इस पावनधरा पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम

लखीमपुर खीरी। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना प्रांगण चंदन चौकी के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को कौशल विकास के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क टूल किट, प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा सीडीओ अभिषेक कुमार के साथ दीप जलाकर कर किया। कार्यक्रम का संयोजन परियोजना अधिकारी यूके सिंह ने किया। आयोजित कार्यक्रम में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अभिषेक कुमार संग कंप्यूटर ट्रेड के 37, ब्यूटीशियन ट्रेड के 30, टेलरिंग ट्रेड के 50ए हैंडीक्राफ्ट ट्रेड के 50 एंजॉयरी ट्रेड की 40 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट एवं प्रमाण पत्र देकर

सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षार्थियों के समक्ष उनको दी जाने वाली टूल किट सामग्रों का अवलोकन कर गुणवत्ता भी देखी। जनजाति क्षेत्र में महिलाएं निभा रही सशक्त भूमिका, किट का इस्तेमाल कर बने आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी: डीएम



कार्यक्रम को संबोधित करतेहुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की इस पावन धरा पर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम! आज सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप कीरतपुर गांव के पुरुष महिलाओएं बच्चेओ बुजुर्गों से मिली हूं। आपको प्रमाणपत्र मिलना इस बात को प्रमाणित कर रहा कि ट्रेड कोर्स को मेहनत लगन से अर्जित किया। महिलाएं बालिकाएं कामे सजग, संघर्षशील और मेहनती हैं। जनजाति क्षेत्र में महिलाएं सशक्त भूमिका निभा रही है। आज मिली किट का भरपूर इस्तेमाल करे। परंपरागत ज्ञान और संस्कृति को न छोडे। इस ट्रेनिंग सेंटर पर कंप्यूटर, ब्यूटीशियन,

सिंह ने परियोजना क्षेत्र में आने वाले थारू जनजाति ग्रामों में किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों को रेखांकित किया। आज आयोजित कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता भी बताई।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना प्रांगण चंदन चौकी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहाए सीडीओ अभिषेक कुमार के साथ फ्लदर छायादार औषधि पोथ का रोपण किया। इस दौरान एसडीएम कार्तिकेय सिंहए बीडीओ संगीता यादवए पीओ यूके सिंह ने भी पौधरोपण किया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अभिषेक कुमार संग एकीकृत जनजाति विकास परियोजना में पहुंचकर परियोजना अधिकारी यूके सिंह से थारू क्षेत्र में संचालित योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, निमाणा कार्यों सहित क्षेत्र के शौधक, आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर हुए प्रयासों की जानकारी ली।

भ्रामक विज्ञापन संबंधी शिकायतों को सार्वजनिक करने की त्वयस्था करे आयुष मंत्रालय: न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आयुष मंत्रालय को एक डैशबोर्ड स्थापित करना चाहिए ताकि भ्रामक विज्ञापनों पर दर्ज शिकायतों और उन पर हुई प्रगति का विवरण उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सके। न्यायालय ने इससे पहले मीडिया में प्रकाशित या प्रदर्शित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के पहलू पर प्रक़श डाला था, जो औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपतजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के विपरीत हैं।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा

कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में उचित आंकड़ों के अभाव के कारण उपभोक्ता असहाय और अंधेरे में रह जाते हैं। इसने कहा, आयुष मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुए एक डैशबोर्ड स्थापित करना चाहिए... ताकि विवरण सार्वजनिक रूप से सामने आ सके।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि कई राज्यों में भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित कई शिकायतें दूसरे राज्यों को भेज दी गई थीं, क्योंकि उन उत्पादों का निष्पान करने वाली कंपनियां वही स्थित थीं। पीठ ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की संख्या, जो पहले 2,500 से अधिक थी, घटकर केवल 130 के आसपास रह गई है और इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए शिकयत निवारण तंत्र का उचित प्रचार नहीं किया गया है। संबंधित मंत्रालय को इस मुद्दे पर गौर करने और दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा।

शीर्ष अदालत की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फर्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस से संबंधित पहलू पर भी विचार किया। उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण (एसएलए) ने 15 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फर्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। हालांकि, प्राधिकरण ने बाद में शीर्ष अदालत में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि विवाद के मद्देनजर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शिकायतों की जांच करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश रद्द कर

दिया गया है। 17 मई को, इसने कहा कि 15 अप्रैल के आदेश को रोक दिया गया और एक जुलाई को निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, आईएमए की ओर से पेश वकील ने निलंबन आदेश को रद्द करने के बारे में पीठ को बताया। पीठ ने पूछा, मौजूदा स्थिति क्या है? उत्तराखंड की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक जुलाई के आदेश के बाद, पतंजलि को एक नया नोटिस जारी किया गया था और एसएलए को 19 जुलाई को पतंजलि से जवाब मिला। जब राज्य के वकील ने कहा कि उन्होंने मामले में कानूनी राय मांगी है, तो पीठ ने पूछा, उन्हें सुनने से पहले मामले को खत्म करने के लिए आपके कितना समय चाहिए? इसने राज्य को अगली सुनवाई की तारीख से पहले कार्य बताओ नोटिस के अनुसरण में आदेश पारित करने और इसकी सूचना पतंजलि को देने को कहा।

दिया गया है। 17 मई को, इसने कहा कि 15 अप्रैल के आदेश को रोक दिया गया और एक जुलाई को निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, आईएमए की ओर से पेश वकील ने निलंबन आदेश को रद्द करने के बारे में पीठ को बताया। पीठ ने पूछा, मौजूदा स्थिति क्या है? उत्तराखंड की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक जुलाई के आदेश के बाद, पतंजलि को एक नया नोटिस जारी किया गया था और एसएलए को 19 जुलाई को पतंजलि से जवाब मिला। जब राज्य के वकील ने कहा कि उन्होंने मामले में कानूनी राय मांगी है, तो पीठ ने पूछा, उन्हें सुनने से पहले मामले को खत्म करने के लिए आपके कितना समय चाहिए? इसने राज्य को अगली सुनवाई की तारीख से पहले कार्य बताओ नोटिस के अनुसरण में आदेश पारित करने और इसकी सूचना पतंजलि को देने को कहा।

ईडी ने आभूषण कंपनी के प्रवर्तकों व पूर्व सांसद के खिलाफ की शिकायत

नागपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक से कार्गूई रूप के की धोखाधड़ी के मामले के संबंध में यहां एक अदालत में पूर्व सांसद इंशराल जैन और उनके बेटे व पूर्व विधान पार्षद मनीष जैन सहित आभूषण की तीन कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली नागपुर की एक विशेष अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 जुलाई को अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।

ईडी ने अदालत ने अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है। ईडी ने तीन आभूषण फर्मों राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लि., आर एल गोएड प्राइवेट लि., मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लि. और उनके प्रवर्तकों/ निदेशकोंजमानतदारों, इंशराल जैन, मनीष जैन और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दी है। अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और राकांपा-शरदचंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार के करीबी सहयोगी इंशराल जैन राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं जबकि उनके बेटे मनीष जैन महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ईडी ने

सीबीआई द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। आभूषण कंपनियों और उनके निदेशकाप्रवर्तक आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जासूसी और आपराधिक कदाचार जैसे अपराधों में शामिल थे और उन्होंने जानबूझकर भारतीय स्टेट बैंक से लिए ऋण का भुगतान नहीं किया, जिससे बैंक को 352.49 करोड़ रूपए (इस राशि पर ब्याज सहित) का नुकसान हुआ। ईडी ने कहा कि जांच के अनुसार, प्रवर्तकों ने ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए और वित्तीय विवरण को बढ़ाने के लिए लेन-देन में हेरफेर भी की। साथ ही कंपनियों के लेखा परीक्षकों के साथ मिलकर कर रियाल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण की आय को निकालने के लिए फर्मों के खातों की पुस्तकों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन दर्ज कराए। पिछले वर्ष ईडी ने राजमल लखीचंद समूह के महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक और ठाणे समेत 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर छापे मारे थे। इस दौरान 24.36 करोड़ के सोना, चांदी, हीरे के आभूषणलौहा-चांदी व 1.21 करोड़ की नकदी जब्त की व अन्य अभियोजन योग्य कागजात बरामद किए थे।

स्कूल में प्रार्थना के बाद कसरत के दौरान 12 बच्चे बेहेश, अस्पताल में भर्ती

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मंगलवार सुबह एक स्कूल में प्रार्थना के बाद कथित रूप से दो बार कसरत और योगासन के लिए मजबूर किए जाने के कारण 12 बच्चे बेहेश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना एटा जिले के मालवान थाना क्षेत्र के हरचंदपुर में पीएमश्री केंद्र्रीय विद्यालय में हुई। डीएम प्रेम रंजन सिंह के अनुसार, स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद कसरत करने के दौरान कुछ बच्चे बेहेश हो गए। प्रधानाचार्या संस्था शरण ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। सिंह ने बताया कि ऐसा आरोप है कि बच्चों से उमस भरी गाथा में जबरन दो बार कसरत और योगासन कराया गया, जिससे यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि आरोप की पड़ताल की जा रही है और बच्चों की जांच के लिए एक मेडिकल टीम स्कूल भेजी गई है। सिंह ने बताया कि फिलहाल 12 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं।

पेज 1 का शेष वायनाड...

भूखलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और संबंधित कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया है। भूखलन में डूबने वाले या मारे गए अधिकांश लोग जिले के चाय और कॉफी बानागों के लायम्स में रहने वाले मजदूर और श्रमिक थे। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पूर्व रबर बोर्ड पी के रामचंद्रन ने द पायनियर को बताया कि प्राकृतिक आपदा एक और सबूत है कि राज्य प्रशासन ने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। वायनाड का संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, ने 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रायबरेली को बरकरार रखने के लिए इसे छोड़ दिया था। शवों के अलावा, बचाव दल को मानव शरीर के क्षत-विक्षत हिस्से भी मिले, जो भूखलन के कारण तेजी से निकले विशाल चट्टानों और पत्थरों से कूच गए थे। समाचार लिखे जाने तक आधे से भी कम शवों की पहचान हो पाई थी। जिले और कोझिकोड के अस्पतालों में इहय-विदारक दृश्यों की तस्वीरें थीं, क्योंकि जीवित बचे लोग दुर्घटना में गायब हुए अपने प्रियजनों और प्रियजनों की तलाश में शवों को स्कैन कर रहे थे। मुख्यमंत्री विजयन ने वित्तीय सहायता के लिए देशों के वैश्विक समुदाय से

न्यायालय ने राकांपा नेता नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत दी

धनशोधन मामला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मंगलवार को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने मलिक को और से पेश वकील को दलीलों पर गौर किया कि वह विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध होगी।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त साॉलिसटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतर्िम चिकित्सा जमानत को स्थाई किया जा सकता है। मलिक को अगस्त 2023 में प्रदान की गई चिकित्सा जमानत को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। मलिक ने बंबई उच्च न्यायालय के 13 जुलाई 2023 के

पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए: शुभेंदु अधिकारी

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सदन के अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय पर कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। भाजपा नेता ने प्रधान सचिव को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बंधु हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, अगर विपक्ष मेरे खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो वह इस पर टिप्पणी करेंगे।

नंदीग्राम से विधायक अधिकारी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीति आयोग जैसे संगठनों की आलोचना करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने अंतिम समय में

राष्ट्रपति मुर्मू 2-3 अगस्त को राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो और तीन अगस्त को राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें तीन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और आदिवासी क्षेत्रों में विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञापित में कहा गया कि यह राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन के एजेंडे में तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा आदिवासी क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

जम्मू में आतंकवाद निरोधक अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी गिरफ्तार

भाषा। जम्मू

जम्मू-कश्मीर के पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और डोडा जिलों के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए तलाश अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा निवासी अब्दुल खलील को आतंकवाद निरोधक अभियान के दौरान पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि खलील के पास से एक पिस्तौल और कुछ गोला-बारूद बरामद किए गए। खलील, प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की

सीमा पार से घुसपैठ कराने के दौरान मार्गदर्शक के तौर पर काम करता था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी के पास से एक मोबाइल फोन और कई पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पुंछ के देहरा की गली इलाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने करीब छह गांवों में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात देहरा की गली के पास सलामपुरा गांव में काले कपड़े पहने दो हथियारबंद संदिग्ध घूमते देखे गए थे।

सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

(सीआरपीएफ) की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों को निचले पंगई इलाके की ओर बचते देखा गया। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान जारी है, लेकिन संदिग्धों का पता फिलहाल नहीं लगा है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार की सुबह पुंछ के जंगलकोट इलाके के सनाई, सुरंग, पट्टन और आसपास के गांवों तथा किश्तवाड़ जिले के द्राबशल्ला इलाके के बांगर-सरूर जंगल में तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि डोडा के देसा और आसपास के जंगलों तथा राजौरी जिले के लाम और नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में भी तलाश अभियान शुरू किया गया।

राज्यों की बार काउंसिल वकीलों के पंजीकरण के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं ले सकती : न्यायालय

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राज्य बार काउंसिल विधि स्नातकों का वकील के रूप में पंजीकरण करने के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं ले सकती, क्योंकि यह हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ व्यवस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देता है। पीठ ने कहा कि समानता के लिए गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य बार काउंसिल (एसबीसी) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) संसद द्वारा निर्धारित राजकोपीय नीति में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और वे सामान्य एवं अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) श्रेणी के विधि स्नातकों का वकीलों के रूप में पंजीकरण करने के लिए क्रमशः 650 रूपए और 125 रूपए से अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं। शीर्ष अदालत ने राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक शुल्क को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने 22 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि ओडिशा में पंजीकरण शुल्क 42,100 रूपए, गुजरात में 25,000 रूपए, उत्तराखंड में 23,650 रूपए, झारखंड में 21,460 रूपए और केरल में 20,050 रूपए है, जबकि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 का तहत 650 रूपए और 125 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। पीठ ने कहा, एसबीसी और बीसीआई निर्धारित पंजीकरण शुल्क और स्टैम्प शुल्क (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य शुल्क के भुगतान की मांग नहीं कर सकती।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, पंजीकरण की पूर्ण विकास करने का अधिकार, अपनी पसंद का पेशा अपनाने और आजीविका कमाने का अधिकार शामिल है। ए सभी चीजें व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत हैं। न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में अत्यधिक पंजीकरण शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क वसूलना कानूनी पेशे में प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है। उसने कहा, पंजीकरण की पूर्व शर्त के रूप में अत्यधिक शुल्क लगाना उन लोगों की गरिमा को ट्रेस पहुंचाता है, जो कानून के क्षेत्र में अपना करियर को आगे बढ़ाने में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं और यह हाशिए पर पड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को कानूनी पेशे में समान भागीदारी को कमजोर करने प्रभावी तरीके से बरकरार रखता है।

पीठ ने मौजूदा पंजीकरण शुल्क संरचना को मौलिक समानता के सिद्धांत के विपरीत मानते हुए एसबीसी और बीसीआई से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शुल्क विभिन्न मर्दों की आड़ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन लिए जा रहे अत्यधिक शुल्क को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने 22 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बंद्योपाध्याय सरकार को अक्षमता को छिपाने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारी ने विपक्ष के सदस्यों के भाषणों के अंशों को बिना किसी वैध कारण के हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और उनकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच, अध्यक्ष ने कहा, अगर विपक्ष मेरे खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो वह इस पर टिप्पणी करेंगे।

नंदीग्राम से विधायक अधिकारी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीति आयोग जैसे संगठनों की आलोचना करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने अंतिम समय में

असूचीबद्ध मामलों पर चर्चा की अनुमति दी लेकिन वे विपक्ष को राज्य में युवाओं और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अधिकारी ने दावा किया, यह सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले, चावल घोटाले, मवेशी घोटाले और रेत घोटाले में फंसी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और मंत्री वर्तमान में जेल में हैं। लेकिन, विपक्ष को सदन में ऐसे मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है। अधिकारी ने बंद्योपाध्याय पर छह तृणमूल विधायकों के शपथग्रहण में राज्यपाल की भूमिका को नजरअंदाज करने और मीडिया की आवाज को दबाकर संविधान का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बंगाल को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ प्रस्ताव की बात पर कहा, हम राज्य के किसी भी विभाजन के खिलाफ हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है।

सहायता मांगी है। टेलीविजन चैनलों ने कई लोगों की फोन पर बातचीत प्रसारित की जिसमें वे रो रहे थे तथा किसी से आकर उन्हें बचाने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि वे या तो अपने घरों में फंस गए या पुलों के बह जाने तथा सड़कों के जलमय होने के कारण उनसे पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ही एक बातचीत में चूरूलमाला शहर निवासी एक महिला को जोर-जोर से रोते हुए यह कहते सुना गया कि उसके घर में कोई व्यक्ति मलबे में फंस गया है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। महिला को यह कहते हुए सुना गया, कृपया कोई आओ और हमारी मदद करो। हमने अपना घर खो दिया है। हमें नहीं पता कि नौशान (स्पष्ट रूप से परिवार का कोई सदस्य) जीवित है या नहीं। वह दलदल में फंस गई है। हमारा घर शहर में ही है...। राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन ने बताया कि भूखलन में घायल हुए 70 से अधिक लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

वैश्विक नितेशक...

यह अंतिम समाधानों से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य भारत की जनशक्ति और उत्पादों को गुणवत्ता और मूल्य के मामले में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। पीएम मोदी ने युवाओं के कोशल और अनुभव को बढ़ाने के लिए शुरू की गई इंटरशिप योजना का भी जिक्र किया, जिससे उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में आए बदलाव को देखते हुए ईपीएफओ अंशदान में प्रोत्साहन का घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों का सरलीकरण, साथ ही बहुउद्देश्यीय लॉजिस्टिक्स पार्क, 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई अंतीत में किए गए कुछ उपाय हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश के 100 जिलों के लिए तैयार निवेश पार्कों प्लग-एंड-प्ले निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये 100 शहर विकसित भारत के नए केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बजट में कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवंटन में वृद्धि, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, किसानों की भूमि के टुकड़ों को नंबर प्रदान करने के लिए भू-आधार कार्ड, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष, महत्वपूर्ण खनिज मिशन और खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों की आगामी नीलामी। उन्होंने कहा कि ये नई घोषणाएं प्रगति के नए रास्ते खोलेंगी। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

राजज...

अनापत्ति प्रमाण पत्र में बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ गोदाम के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बेसमेंट के अन्य उपयोगों के इस्तेमाल करने के चलते जानमाल का नुकसान हुआ। स्थानीय

निवासियों ने कहा कि कोचिंग के बेसमेंट में प्रवेश द्वार बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल लॉक सिस्टम के साथ था और घटना के समय छात्र समय पर बाहर नहीं आ सके।

योगी सरकार...

जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही संशोधित अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती बना दिया गया है। यूपी सरकार ने इस बिल को सोमवार को विधानसभा में पेश किया था और मंगलवार को यह पास हो गया। अब इसे विधान परिषद में भेजा जाएगा। सदनों से मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था इस बिल में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन के जरिए पिछले बिल को सजा और जुर्माने के मामले में और मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदिन्यथा ने कश्चित् जब्दन धर्म परिवर्तन के लिए कुछ हिंदू संगठनों द्वारा गढ़े गए शब्द लव जिहाद पर अंकुश लगाने के इरादे से यह पेश की थी। नवंबर 2020 में जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए एक अध्यायश जारी किया गया था और बाद में, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकारनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम –2021 लागू हो गया। संसद के बाहर बिल पर टिप्पणी करते हुए

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उनके पास और क्या है, वे कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वे सांप्रदायिक राजनीति के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिम कोर्ट ने इस साल मई में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून कुछ हिस्सों में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्यक्ष धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता प्रतीत हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था इस बिल में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन के जरिए पिछले बिल को सजा और जुर्माने के मामले में और मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदिन्यथा ने कश्चित् जब्दन धर्म परिवर्तन के लिए कुछ हिंदू संगठनों द्वारा गढ़े गए शब्द लव जिहाद पर अंकुश लगाने के इरादे से यह पेश की थी। नवंबर 2020 में जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए एक अध्यायश जारी किया गया था और बाद में, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकारनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम –2021 लागू हो गया। संसद के बाहर बिल पर टिप्पणी करते हुए

बेहतर नीतियों...

8.2 प्रतिशत रही है और भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख देश का दर्जा बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, हम राजकोपीय मजबूती के तहत 2025–26 में राजकोपीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। 3। चालू वित्त वर्ष में इसके 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका श्रेय बेहतर अर्थव्यवस्था प्रबंधन को जाता है। वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों के सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटन कम करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट दस्तावेज इसके उलट बर्‍या करता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष से ज्यादा है। बीच-बीच में हिंदी में चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, विपक्षी सदस्यों ने कहा कि बजट में केवल दो राज्यों को पैसा दिया गया है। यह कुछ और नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करने का काम है। उन्होंने कहा, 2004–05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं था...2010–11 के बजट में 19 राज्यों का जिक्र नहीं था, 2014–15 में 10 राज्यों का जिक्र नहीं है। सीतारमण ने कहा, यह सबको पता है कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संग्रम) सरकार को गलत नीतियों से मंहगाई दहाई अंक के कब्जे चली गई थी लेकिन आज यह काफी हद तक नियंत्रण में है। यह सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा है।

मनु ने रचा इतिहास, भारतीय हॉकी टीम ने जगाई उम्मीद

● सरबजोत के साथ दूसरा पदक जीता

भाषा । शेटराज

युवा निशानेबाज मनु भाकर ने मंगलवार को यहां स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया जिन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत को पेरिस खेलों में दूसरा कांस्य पदक दिलाया। भारतीय हॉकी टीम ने भी अजेय अभियान जारी रखा तथा बैडमिंटन में सात्विकसाईंराज रंकीरेड्डी और चिराम शेट्टी की जोड़ी अपने ग्युप में शीर्ष पर रही। पर मुक्केबाजी में देश को निराशा हाथ लगी जबकि तीरंदाजों का दिन मिला जुला रहा मनु और सरबजोत ने जीता कांस्य पदक: भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कोरिया के ली चोन्ही और ओ ए जिन को 16 . 10 से हराकर देश को दूसरा पदक दिलाया। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य



पंघाल और जैस्मीन का ओलंपिक अभियान खत्म

पेरिस। भारत के अनुभवी मुक्केबाज अमित पंघाल मंगलवार को यहाँ पेरिस ओलंपिक की मुक्केबाजी स्पर्धा में पुरुष 51 किग्रा वर्ग में और पदार्पण करने वाली महिला मुक्केबाज जैस्मीन लम्बोदिया 57 किग्रा वर्ग में हारकर बाहर हो गए। पंघाल का पेरिस ओलंपिक अभियान राउंड 16 में अग्रणी खेलों के पैगियन और तीसरे वरीय जाँबिया के पेट्टिक पिन्डुबा से 1-4 से हारकर समाप्त हुआ जबकि जैस्मीन पिन्डीपीस वीं तोक्यो ओलंपिक की रगत पदक विजेता और पूर्व विश्व चैम्पियन जेस्टी पेट्टिसियो से 0-5 से हारकर बाहर हो गई। विश्व चैम्पियनशिप 2019 के रगत पदक विजेता पंघाल को पहले दौर में बाई मिली थी। वह तोक्यो ओलंपिक में भी इसी तरह हारकर हुए थे जिसने भी उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी। तोक्यो के प्रदर्शन के बाद वह राष्ट्रीय टीम से बाहर हो थे और टीपक मोरिया के दो खालीपट्टर ने चोट नही लहसिल करने के बाद उन्हें अंतिम ओलंपिक खालीपट्टर के लिए चुना गया था। जाँबिया के पेट्टिकिने थुरुसे से ही आक्रमक रूस अखिरवार करते हुए टक्का बनाया और पंघाल को वापसी का मौक नही दिया।



जीता था। तोक्यो ओलंपिक में मनु पिस्टल में खराबी आने के कारण फाइनल के लिए खालीपट्टर नहीं कर सकी थी लेकिन यहाँ दो पदक जीतकर उन्होंने हर जखम पर महम लगा दिया। ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फर्टा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे लेकिन वह उपलब्धि आज्ञादी से पहले

की थी। मनु अब दो अगस्त को 25 मीटर महिला पिस्टल खालीपट्टर के लिय उतरेंगी और उनके पास तीसरा पदक जीतने का भी मौका है। सरबजोत 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत वर्ग में खालीपट्टर में 577 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहे थे और फाइनल में जगह नहीं बना सके थे। मनु और सरबजोत ने खालीपट्टर दौड़ में 580 स्कोर करके कांस्य पदक के मुकाबले में

जगह बनाई थी। वहीं भारतीय ट्रेप निशानेबाजी में प्रदर्शन निराशाजनक रहा जिसमें पृथ्वीराज तोंडमन खालीपट्टर में 21वें स्थान पर रहे जबकि महिला वर्ग में राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह पहले दिन खालीपट्टर के तीन राउंड के बाद 21वें स्थान पर रही जबकि श्रेयसी 22वें स्थान पर रही। दोनों बुधवार को खालीपट्टर के दो और राउंड खेलेंगी। हरमनप्रीत के दो गोल से भारतीय हॉकी टीम जीती : कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल और गोलकीपर पी आर श्रीजेश के शानदार प्रदर्शन को मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आयरलैंड पर 2-0 से जीत हासिल की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 11वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर पहला और 19वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। पहले मैच में न्यूजीलैंड पर 3 . 2 से मिली जीत में हरमनप्रीत ने 59वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर विजय गोल दागा था। वहीं रियो ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना के खिलाफ सोमवार को 59वें मिनट में ही उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रोक करके भारत को हार से बचाते हुए मैच 1-1 से ड्रॉ कराया था। भारत अब दो अगस्त को आस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।

ओलंपिक पदक तालिका				
देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	6	6	2	14
जापान	6	2	4	12
फ्रांस	5	8	3	16
ऑस्ट्रेलिया	5	4	0	9
कोरिया	5	3	2	10
अमेरिका	3	8	9	20
ग्रेट ब्रिटेन	3	5	3	11
इटली	2	3	3	8
कनाडा	2	1	2	5
हांगकांग	2	0	1	3
भारत	0	0	2	2



पेरिस ओलंपिक: भारत का पांचवें दिन का कार्यक्रम

पेरिस। भारत का पेरिस ओलंपिक में बुधवार को यहाँ पांचवें दिन का कार्यक्रम (भारतीय समयानुसार) इस प्रकार है। निशानेबाजी: 50 मीटर राइफल थी पोनीशन पुरुष खालीपट्टर; शेर्या प्रताप सिंह तोमार और खालिफ कुसाते - टोपहर 12:30 बजे , ट्रेप महिला खालीपट्टर: श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी - टोपहर 12:30 बजे , बैडमिंटन: महिला एकल (गुप घरा): पीवी सिधू बनाम मिस्किन कुब्बा (एस्टोनिया) - टोपहर 12:50 बजे , पुरुष एकल (गुप घरा): लक्ष्य सेन बनाम जोनाटन फ्रिस्टी (इंडोनेशिया) - टोपहर 1:40 बजे, पुरुष एकल (गुप घरा): एणस प्रणय बनाम डुकु घाट (वियतनाम) - रात 11 बजे, टेबल टेनिस: महिला एकल (अंतिम 32 गैट): श्रीजा अक्षुा बनाम निजाम जेग (सिंगापुर) - टोपहर 2:20 बजे मुक्केबाजी: महिला 75 किग्रा (अंतिम 16 दौर): लवलीना बोरोवोहेन बनाम सुनिवा हेंकरटेड (नीदर) - टोपहर 3:50 बजे , पुरुष 71 किग्रा (अंतिम 16 दौर): निशात देव बनाम जोस गेंब्रियल सेडोन (कोलंबिया) (इक्वडोर) - रात 12:18 बजे। तीरंदाजी: महिला एकल: अंतिम 64 घरा: टीपिका कुमारी - टोपहर 3:56 बजे, पुरुष एकल: अंतिम 64 घरा: तसपादी राय - रात 9:15 बजे, युएसबी: व्यक्तिगत डेडन गा पी दूसरा दिन: अनुया अयावाल - टोपहर:30 बज

पेरिस ओलंपिक पर बारिश के बाद अब लू का खतरा

पेरिस। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत उपजाऊन समावेश में बारिश के साथ हुई थी जिसने दृष्टिको के साथ खिलाड़ियों को भी तट कर दिया था, लेकिन अब यहाँ लू का खतरा मंड़रने लगा है। मंगलवार को यहाँ तेज गर्मी महसूस की गई और राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने कहा कि प्रायः के अधिकांश हिस्से ने लू की चेतावनी जारी की गई है तथा पेरिस और आसपास के इलाकों ने तापमान 35 और 38 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुँचने की संभावना है। प्रायः के दक्षिणी हिस्से ने गर्मी अधिक कर बढ़ना संभव है। इसने मूल्यांकन सागर का तटीय शहर मॉसिले भी शामिल है, जो फुर्बल और नौकयन जैसी ओलंपिक प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है।

रूस के खिलाड़ियों की सीमित संख्या से यूक्रेन को है खुशी

पेरिस। यूक्रेन के ओलंपिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने इस बात पर खुशी जताई है कि पेरिस ओलंपिक में रूस के खिलाड़ियों की संख्या बेदद कम है और जो खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं वे भी तटस्थ के रूप में खेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग ढाई साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ओलंपिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बालिम गुट्टेस्ट ने एक साक्षात्कार में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि फ्रेजलिन (रूस) की सेना द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन ने दुनिया भर के खेल आयोजनों में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों की संख्या को कम करने का प्रयास शुरू किया और पेरिस में इसका समाधानक अंतर दिख रहा है।

डीजे ने ऑनलाइन दुर्लवहार के लिए कानूनी शिक्कत दर्ज कराई

पेरिस। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह को लेकर उठे विवाद ने मंगलवार को कानूनी मोड़ ले लिया, जब इस समारोह को प्रस्तुति देने लगे थे तब से कम कि ऑनलाइन धमकिया मिलने के कारण उनका वरीय इस्वी शिक्कत दर्ज कर रहा है। बलात्कार हुए के वकील ने डीजे के इंटरव्यू पर पोस्ट किया एक एक पत्र में कम कि हुए को जान से मारने, यातना देने और बलात्कार की धमकिया मिल रही है। आलोचक उपजाऊन समावेश के उस दृष्टिको के लिए आलोचना कर रहे हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि इसमें लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग टा लारट सपर का मजाक उड़ाया गया है।

सात्विक-चिराम गुप में शीर्ष पर, अश्विनी और तनीषा का अभियान खत्म

भाषा । पेरिस

एशियाई खेलों की चैम्पियन और पदक की दावेदार सात्विकसाईंराज रंकीरेड्डी और चिराम शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को यहाँ पेरिस ओलंपिक की बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में मुहम्मद रियान अर्दियातो और फजर अल्फियान की इंडोनेशिया की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर गुप सी में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि अश्विनी पोन्पाया और तनीषा क्रापेटो का महिला युगल में अभियान लगातार तीसरी हार के साथ खत्म हुआ। दुनिया की पांचवें नंबर की सात्विक और चिराम को भारतीय जोड़ी ने अर्दियातो और अल्फियान की दुनिया की सातवें नंबर की जोड़ी को 40 मिनट में 21-13, 21-13 से हराया। ए दोनों जोड़ियाँ पहले ही अंतिम आठ में जगह बना चुकी थी और इस मुकाबले से गुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का फैसला हुआ। भारतीय जोड़ी ने गुप में अपने सभी

नौकयन खिलाड़ी बलराज फाइनल में पांचवें स्थान पर, 13वें से 24वें स्थान के लिए खेलेंगे



गयने है कि ए खिलाड़ी 13वें से 24वें स्थान के लिए उतरेंगे। पवार डेपेजिन टैप वीं रूस में दूसरे स्थान पर रहकर खरट फाइनल में पहुँचे थे। वह शनिवार को पहले दौर की हीट रूस में चौथे स्थान पर रहकर डेपेजिन ने पहुँचे थे। चार खरट फाइनल हीट में शीर्ष तीन पर रहने वाले खिलाड़ी सेमीफाइनल ए . बी में पहुँचे जो पदक के लिए मुकाबला करेंगे।

यू की दुनिया की 26वें नंबर की जोड़ी के खिलाफ 38 मिनट में 15-21, 10-21 से हार झेलनी पड़ी गुप सी से किम सो यिऑंग और कॉंग ही योंग की दक्षिण कोरियाई जोड़ी तथा नामी मात्सुयामा और चिहारु शिदा की जापान की चौथी वरीय जोड़ी दो स्थान पर रहते हुए खरट फाइनल में जगह बनाई। इन दोनों जोड़ियों ने



अश्विनी और तनीषा की जोड़ी को हराया था। पुरुष युगल में भारत और इंडोनेशिया की जोड़ी के बीच शुरुआत से ही प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन सात्विक और चिराम की जोड़ी पूरे मुकाबले के दौरान एक बार भी नहीं पिछड़ी। दोनों जोड़ियों ने तेज खेल दिखाया।

ट्रेप निशानेबाज तोंडमन खालीपट्टर में 21वें स्थान पर रहे, महिलाएं पिछड़ी

शेटराज (फ्रांस)। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज तोंडमन ने यहाँ पुरुष ट्रेप स्पर्धा के खालीपट्टर में अंतिम दो राउंड में परफेक्ट 25 का निशाना लगाया लेकिन इसके बावजूद 21वें स्थान पर रहे। तोंडमन पांच राउंड में 125 शॉट में से कुल 118 का स्कोर ही बना सके जिससे वह 30 निशानेबाजों में 21वें स्थान पर रहे। शीर्ष छह निशानेबाज फाइनल के लिए खालीपट्टर करके हैं। सैंतीस साल के तोंडमन ने पांच राउंड में 22, 25, 21, 25 और 25 अंक बनाए जिनमें से दो राउंड शेटराज शूटिंग सेंटर में खालीपट्टर के दूसरे दिन हुए। पुरुष ट्रेप स्पर्धा में एकमात्र भारतीय निशानेबाज तोंडमन ने खालीपट्टर दौड़ के पहले दिन 22, 25 और 21 का स्कोर बनाया जिससे वह तब 30वें स्थान पर थे। महिला ट्रेप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह पूरी तरह से निशाने से चूक गईं। राजेश्वरी ने पहले दिन खालीपट्टर के तीन राउंड में 75 अंक से 68 शॉट लगाए और 30 प्रतियोगियों में 21वें स्थान पर रही जबकि श्रेयसी 22वें स्थान पर रही। फाइनल के लिए शीर्ष छह निशानेबाज तब होने से पहले दोनों बुधवार को खालीपट्टर के दो और राउंड खेलेंगी।

भजन अंतिम 16 में पहुंची, अंकिता का महिला एकल में सफर खत्म

भाषा । पेरिस

भारतीय तीरंदाज भजन कौर ओलंपिक के महिला एकल वर्ग में मंगलवार को यहाँ पोलैंड की वियोलेटा मैसजोर पर 6-0 की विजय हासिल करके कांस्य पदक जीतने में सफल रही। भजन ने अंतिम 32 दौर में मैसजोर को हराने के साथ अंकिता भक्त की हार का बदला चुकता किया। पोलैंड की इस



तीरंदाज ने इससे पहले अंतिम 64 चरण के मैच में अंकिता को 6-4 से हराया था। भजन ने दिन के अपने

शुरुआती मैच में इंडोनेशिया की साइफा नूरफोफा कमाल को 7-3 से शिकस्त देने के बाद वियोलेटा के खिलाफ अपनी लय जारी रखते हुए एकरफा जीत दर्ज की। भजन ने वियोलेटा के खिलाफ पहले सेट और तीसरे सेट में भी जीत हासिल की और दूसरे सेट में दो निशाने लगाकर अपना दखवा बनाया। उन्होंने 28-23, 29-26, 28-22 से आसान जीत दर्ज की।

मंधाना, रेणुका ठाकुर रैकिंग चौथे और पांचवें स्थान पर

दुबई। भारत की स्मृति मंधाना आईसीसी टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुँच गई जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों में पांचवें स्थान पर है। सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में 60 रन बनाए। उन्हें एकपायदान का प्रयास मिला और उनके 743 रैंकिंग अंक हैं। गेंदबाजों में रेणुका 722 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है जिन्होंने टूर्नामेंट में सात विकेट लिए थे। इनके ही साथ एसलेटोन शीर्ष पर है जबकि टीटिन शान तीसरे स्थान पर है। बल्लेबाजों में आस्ट्रेलिया की बेथ नूनी और तालियावा नेक्सा पहले दो स्थान पर है।

आडवाणी, सितलवा वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैम्पियनशिप में भाग लेने

मुंबई। वरुंडे वरुंडे चैम्पियन पंकज आडवाणी तथा नौजुद एशियाई और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैम्पियन ध्रुव सितलवा तीन अगस्त से यहाँ शुरू होने वाली वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैम्पियनशिप में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन तीन श्रेणियों सीनियर बिलियर्ड्स, सीनियर स्नूकर और जूनियर स्नूकर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नौजुद राष्ट्रीय स्नूकर चैम्पियन सीरथ चोव्हा, आदित्य मेहता, लक्ष्मण रावत, रमेश शाह, धन हर्षिया, आलोक कुमार्, सिद्धार्थ पांडेय और प्रश्रुकामा भी हिस्सा लेने सीनियर स्नूकर चैम्पियन को दो लाख रपय और उपविजेता को 1.2 लाख रपय की पुरस्कार राशि मिलेगी।

डीएसएस वलब की जीत में शरीफ का आलाराउड खेल

लखनऊ। नैन ऑपंड नैन मो.शरीफ 2 विकेट, नाबाद 52 रन के आलाराउड खेल से डीएसएस वलब ने पांचवीं श्रीलंका सिंह स्नाकर टी20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में मेहला वलब को 4 विकेट से पराजित किया। पार्थ रिपब्लिक गार्ड्स पर मेहला वलब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाया। टीम को सलामी बल्लेबाज अजितान 62 रन, व विनीत सिंह ने 58 रन बनाए। अंकुर व शरीफ को 2-2 विकेट मिले। जवाब में डीएसएस वलब ने लक्ष्य का पीछ करते हुए निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाकर नौवें जीत लिया। अब्दुल्लाह जमाली ने 57 और शरीफ ने 52 रन बनाए।

श्रीलंका क्रिकेट के नए संविधान का मसौदा तैयार करवाएगी सरकार

कोलंबो। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने कानूनी सलाहकार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के लिए नए संविधान के मसौदे पर काम करने के निर्देश देने का फैसला किया है। इस समिति को चिप्रसिरी समिति के नाम से जाना जाता है। इसने सिफारिश की थी कि एसएलसी को 18 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के नए ढांचे के लिए सरकार का हस्तक्षेप तब हुआ जब तत्कालीन खेल मंत्री सेवन रमसिंधे ने वर्तमान एसएलसी प्रशासन को बर्खास्त कर दिया और उसकी जगह एक अंतरिम समिति बना दी।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गांगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गांगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सूझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर गुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।